22वीं कांग्रेस का राजनीतिक प्रस्ताव

(18 से 22 अप्रैल 2018 तक हैदराबाद में संपन्न पार्टी कांग्रेस में स्वीकृत)

हमारी पार्टी की 21वीं कांग्रेस के बाद के दौर में भारत में राजनीतिक दक्षिणपंथ का और सुदृढ़ीकरण हुआ है। यह भाजपा-नीत एनडीए सरकार देश और हमारी जनता के खिलाफ एक विद्वेषपूर्ण चौतरफा हमला छेड़े हुए है। वह नवउदारवादी आर्थिक नीतियों पर आक्रामक तरीके से चल रही है; विभिन्न रूपों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तीखा कर रही है; संसदीय जनतंत्र तथा संस्थाओं के खिलाफ बढ़ते हुए तानाशाहीपूर्ण हमले कर रही है; और अमरीका तथा साम्राज्यवाद के जूनियर रणनीतिक साझीदार के भारत के दर्जे को पुख्ता कर रही है। भारतीय शासक वर्ग द्वारा अमरीकी साम्राज्यवाद के फरमानों के सामने हमारे देश के तथा जनता के हितों के इस समर्पण का आकलन, अंतर्राष्ट्रीय हालात में उस महत्वपूर्ण घटनाविकास की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए, जिसका आज के भारत के हालात पर सीधे असर पड़ रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति

1.1 21वीं कांग्रेस के बाद की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) हालांकि मामूली वैश्विक आर्थिक बहाली की भविष्यवाणियां की जा रही हैं, वैश्विक पूंजीवाद का व्यवस्थागत संकट, जिसकी अभिव्यक्ति 2008 के वित्तीय महासंकट में हुई थी, बना ही हुआ है।

(2) इसके चलते, कटौती की नीतियां लागू किए जाने के साथ, सभी पूंजीवादी देशों में जनता के विशाल बहुमत के आर्थिक शोषण में और तेजी आ रही है तथा जनतांत्रिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में इन हमलों के खिलाफ विरोध कार्रवाइयों तथा संघर्षों का बढ़ना जारी है।

(3) वैश्विक पूंजीवाद के इस मुसलसल जारी संकट के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर और अलग-अलग देशों के स्तर पर भी, आर्थिक असमानताएं और बढ़ी हैं।

(4) अपने वैश्विक वर्चस्व को सुदृढ़ करने तथा आर्थिक संकट के नकारात्मक असर से उबरने की अपनी कोशिशों में अमरीकी साम्राज्यवाद, खासतौर पर राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य हस्तक्षेपों के जरिए, और बढ़ी हुई चौतरफा आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है।

(5) लातीनी अमरीका में विभिन्न देशों में अमरीकी राजनीतिक तथा सैन्य हस्तक्षेपों के साथ एक गंभीर टकराव हो रहा है। इस महाद्वीप में वामपंथी नेतृत्ववाली सरकारों को अस्थिर करने के लिए और जनता के बीच लोकप्रिय साम्राज्यवादविरोधी ज्वार को पलटने के लिए, अमरीका अपने तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है।

(6) इस दौर में, योरप में घोर दक्षिणपंथी नवफासीवादी ताकतों के उभार के साथ, अनेक देशों में राजनीतिक दक्षिणपंथ की ओर झुकाव और बढ़ा है। अमरीका के राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रम्प के बैठने से, जो अमरीकी सत्ताधारी वर्गों के सबसे प्रतिक्रियावादी हलकों का प्रतिनिधित्व करता है, यह रुझान और ताकतवर हुआ है।

(7) साम्राज्यवादी खेमे की सुसंबद्धता और साम्राज्यवाद के आपसी अंतर्विरोधों के मंद पड़ने की जिस स्थिति को हमने अपनी 21वीं कांग्रेस में दर्ज किया था, नवउदारवाद के इस लंबे संकट के असर के चलते, इस दौर में कमजोर हुई है और साम्राज्यवादी केंद्रों के बीच टकराव के नये बिंदु तथा अंतर्विरोध उभर रहे हैं।

(8) हमारे जैसे कुछ देशों में आए एक मुखर अमरीकापरस्त झुकाव के चलते, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था में बहुध्रुवीयता के पक्ष में रुझान को नयी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

(9) जलवायु परिवर्तन पर संधि जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और विश्व व्यापार संगठन का भविष्य एक अनिश्चितता के चरण में प्रवेश कर गया है क्योंकि अमरीका ने इकतरफा तरीके से ऐसी कुछ संधियों से हाथ खींच लिए हैं और वह बहुपक्षीय व्यवस्थाओं की जगह पर, स्वतंत्र देशों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्थाओं को ही तरजीह दे रहा है।

(10) हमारे पड़ौस के सभी देशों में बहुत महत्वपूर्ण घटनाविकास हो रहे हैं, जिनका अच्छे पड़ौसियों वाले हमारे संबंधों पर सीधा असर पड़ता है।

(11) **समाजवादी देश:** इस दौर में चीन की शक्ति तथा उसके वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी हुई है। वियतनाम तथा क्यूबा की अर्थव्यवस्थाओं ने ठीक-ठाक और वहनीय वृद्धि हासिल की है। कोरियाई जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) के मामले में मुख्य मुद्दा, उसके नाभिकीय कार्यक्रम तथा मिसाइलों की तैनाती के गिर्द केंद्रित है।

(12) अक्टूबर क्रांति की शताब्दी के पालन और इसके साथ ही कम्युनिस्ट तथा वर्कर्स पार्टियों की सालाना अंतर्राष्ट्रीय बैठकों ने, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट एकजुटता को स्वर देना जारी रखा है।

वैश्विक पूंजीवादी संकट

1.2 2008 के वित्तीय महासंकट के धक्के से आया वैश्विक पूंजीवादी संकट पूंजीवादी व्यवस्था को एक के बाद दूसरे संकट में धकेलता जा रहा है। वैश्विक पूंजीवाद 20वीं सदी के अंतिम दशक में हासिल हुए वृद्धि दर के स्तर तक बहाली नहीं कर पाया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के नेतृत्व में साम्राज्यवादी विश्वीकरण पूंजी के संचय की प्रक्रिया को तीव्र करना जारी रखे हुए है। यह काम वह उन तरीकों के जरिए कर रहा है, जिन पर हमने अपनी 20वीं कांग्रेस में स्वीकृत हुए विचारधारात्मक प्रस्ताव में विचार किया था। यह तरीका है, 'जबरिया हड़पने के जरिए संचय।' यह प्रक्रिया पूंजीवादी शोषण को और तेज कर रही है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक असमानताओं में तथा इसके चलते विश्व आबादी के विशाल बहुमत की बदहाली में अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ोतरी हुई है। यह नवउदारवाद के ही संकट की ओर ले जा रहा है।

1.3 2017 के अक्टूबर में आए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकॉनमिक आउटलुक में वैश्विक जीडीपी वृद्धि की एक आशावादी भविष्यवाणी की गई है। उसकी प्रत्याशा है कि 2016 की 3.2 वृद्धि बढ़कर यह आंकड़ा 2017 में 3.6 तथा 2018 में 3.7 फीसद हो जाएगा और 2020-21 तक 3.8 फीसद पर पहुंच जाएगा। फिर भी यह आंकड़ा वैश्विक वित्तीय महासंकट से पहले के दशक के मुकाबले कम रहेगा, जब वृद्धि का औसत रुझान 4 फीसद से ऊपर रहा था। एक आशावादी अनुमान पेश करते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी 2017 के अप्रैल की आगाही को दोहराया है कि, 'मध्यम अवधि के जोखिम अब भी नीचे खिसकने

के पक्ष में झुके हुए हैं।'

1.4 **वैश्विक बेरोजगारी:** जीडीपी की वृद्धि दर में मामूली सुधार के साथ अक्सर यह उम्मीद की जाती है कि पीछे-पीछे रोजगार में वृद्धि भी बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि विकसित पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी की दर, 2010 के 8.3 फीसद से घटकर 2017 में 5.7 फीसद फीसद रह गयी थी। बहरहाल, बेरोजगारी की दर में इस कमी का अर्थ मेहनतकश जनता की जीवन दशाओं में भी इस हिसाब से बेहतरी आना नहीं है। इसका पता इस तथ्य से लगता है कि मजदूरी तथा आयों में औसत बढ़ोतरी, 2016 में 1.6 फीसद तथा 2017 में 2.3 फीसद थी, जो संकट से पहले के, 1999-2008 के दशक में रही औसतन 3.4 फीसद वृद्धि के मुकाबले यह कम है। दूसरे शब्दों में यह मामूली वृद्धि भी अस्थिर है क्योंकि इस वृद्धि से आ रहे रोजगार न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से सीमित हैं बल्कि गुणात्मक रूप से भी दरिद्र हैं। 'मजदूरी की अनमनीयताओं' को कम करने के लिए, 'श्रम बाजार का लचीलापन' लाने के नाम पर बढ़ते पैमाने पर कम आय देने वाले पार्ट टाइम कैजुअल रोजगार या स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरल भाषा में कहें तो वृद्धि में मामूली बहाली मेहनतकश जनता के ज्यादा निचोड़े जाने की कीमत पर हो रही है और आर्थिक शोषण तेज कर मुनाफे का अधिकतम किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है, जो कि पूंजीवाद का शास्त्रीय चरित्र ही है।

1.5 इस तरह की मामूली बहाली का, जिसकी पहचान जीडीपी के अनुपात के रूप में वास्तविक मजदूरी के अगर घट नहीं रहे होने तब भी जस के तस बने रहने से होती है, नतीजा यह है कि अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग इसके लिए काफी नहीं बढ़ रही है कि मालों के उत्पादन में कहीं ज्यादा निवेश को बढ़ावा दे सके।

1.6 कृत्रिम मेधा (एआइ) तथा रोबोटिक्स के क्षेत्र में प्रगति ने स्वचालन के उपयोग को सरल पुनरावृत्तिमूलक कामों तथा फैक्ट्री फ्लोर से बहुत आगे बढ़ा दिया है। कृत्रिम मेधा के उभरते हुए उपकरणों का प्रभाव अनेकानेक कामों तथा रोजगारों पर पड़ सकता है, जिसमें टैक्सी व ट्रक चलाने से लेकर, ''बौद्धिक'' मजदूरों के सफेदपोश काम तक शामिल हैं। मजदूर वर्ग के आंदोलन को इन प्रौद्योगिकियों की नयी चुनौतियों का समुचित नारों, लक्ष्यों तथा मजदूरों को संगठित करने की पद्धतियों से मुकाबला करना होगा।

1.7 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के नेतृत्व में नवउदारवादी व्यवस्था के तहत, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के हाथों में भारी मात्रा में तरलता जमा हो गयी है, जिसे वे

बाजारों में नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि घरेलू मांग में वृद्धि का अभाव निवेश को कुंठित कर रहा है। ***फाइनेंशियल टाइम्स*** के अनुसार दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंक, जैसे अमरीकी फैडरल रिजर्व, योरपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा स्विस व स्वीडिश सेंट्रल बैंक, इस समय 150 खरब डालर (लगभग 995 लाख करोड़ रु0) से ज्यादा की परिसंपत्तियां अपने हाथों में लिए बैठे हैं, **जो 2008 के वित्तीय महासंकट से पहले के मुकाबले में चार गुना से ज्यादा ऊपर है**। इसने परिसंपत्ति मूल्य मुद्रास्फीति को ऊंचा बनाए रखा है, जबकि आम मुद्रास्फीति कम बनी रही है। यह ऐसे हालात की ओर ले जा रहा है जहां एक बार फिर 'बुलबुला' फूट सकता है और एक और वित्तीय संकट भड़का सकता है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के नेतृत्व में चल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में है, जहां वित्तीय संकट का एक और चक्र सामने आ सकता है।

बढ़ती असमानताएं

1.8 इस आर्थिक संकट ने नवउदारवाद द्वारा पैदा की गयी असमानताओं में चिंतित करने वाली तेजी को, जिसे कि हमने अपनी 21वीं पार्टी कांग्रेस में दर्ज किया था, और भी बढ़ा दिया है। असमानताओं में यह बढ़ोतरी, वैश्विक स्तर पर भी हुई है और अलग-अलग देशों के स्तर पर भी। अमीरों के और अमीर होने, जबकि गरीबों के और निचोड़े जाने की प्रक्रिया में तेजी आना जारी है। क्रेडिट सुइस, 2017 के अनुसार, विश्व आबादी के 2.7 फीसद हिस्से के हाथों में, विश्व आय का 70.1 फीसद हिस्सा था। दूसरी ओर, विश्व आबादी के 85.6 फीसद के हाथों में विश्व आय का सिर्फ 8.6 फीसद हिस्सा था।

1.9 वर्ल्ड इनीक्वेलिटी लैब (डब्ल्यूआइएल) द्वारा तैयार की गयी, 2018 की विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 1 फीसद ने, 1980 के बाद से वैश्विक आय बढ़ोतरी के, सबसे नीचे वाले 50 फीसद के मुकाबले दोगुने हिस्से पर कब्जा कर लिया था। सबसे नीचे के 50 फीसद और सबसे ऊपर के 1 फीसद के बीच में आने वाले लोगों के मामले में, आय में वृद्धि सुस्त और यहां तक कि शून्य तक रही है। इस रिपोर्ट में जिन देशों का अध्ययन किया गया है उनमें से भारत में, सबसे ऊपर के 10 फीसद के आय के हिस्से के पैमाने से, असमानताओं में बढ़ोतरी की दर सबसे तेजी से बढ़ी है। नवउदारवादी सुधारों के लागू किए जाने के बाद से, 1980 और 2015 के बीच, आय में शीर्ष 10 फीसद का हिस्सा 30 फीसद से जरा से ऊपर के स्तर से बढ़कर, करीब 60

फीसद तक पहुंच गया है।

बढ़ती लोकप्रिय विरोध कार्रवाइयां

1.10 विश्व आबादी के विशाल बहुमत की बदहाली बढ़ने के इन हालात में, जिसके साथ ही साथ मजदूर वर्ग पर, ट्रेड यूनियनों पर, किसानों पर और जनतांत्रिक अधिकारों तथा नागरिक स्वाधीनताओं पर बढ़ते हुए हमले हो रहे हैं, विकसित पूंजीवादी देशों से लेकर विकासशील देशों तक, दुनिया भर में लोकप्रिय संघर्ष फूट रहे हैं। बहरहाल, जैसाकि हमने अपनी 21वीं कांग्रेस में दर्ज किया था, ये संघर्ष सारत: अपने चरित्र में रक्षात्मक हैं। वे इस अर्थ में रक्षात्मक हैं कि मुख्यत: उनका लक्ष्य मौजूदा जीवन स्तर तथा जनतांत्रिक अधिकारों की और हमलों तथा क्षय से रक्षा करना है। **बहरहाल, ये बढ़ती विरोध कार्रवाइयां ही ऐसे आधार हैं जिनके बल पर आने वाले समय में, पूंजी के शासन के खिलाफ संघर्षों को सुदृढ़ करना होगा।**

1.11 **नवउदारवाद का संकट :** वैश्विक वित्तीय महासंकट के आने के दस साल बाद, अब बड़ी संख्या में लोगों के लिए तथा खासतौर पर विकसित पूंजीवादी देशों में बड़ी संख्या में लोगों के लिए यह स्पष्ट हो गया है कि नवउदारवाद के उभार का नतीजा क्या हुआ है। इसने, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जहां अधिकांश आर्थिक विकास तथा वृद्धि को बहुत ही छोटे से अल्पमत द्वारा हथिआया जा रहा है, जिसके चलते जनता के विशाल बहुमत के हिस्से में बढ़ती बदहाली आ रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के पहले ढाई दशकों में विश्व पूंजीवाद ने वृद्धि का एक गतिशील दौर देखा था, जिसे अक्सर 'पूंजीवाद का स्वर्ण काल' कहा जाता है। 1948 से 1972 के बीच अमरीका में, उसकी जनता का हरेक हिस्सा अपने जीवन स्तर में सुधार को महसूस कर रहा था। बहरहाल, 1972 से 2013 के बीच, सबसे नीचे के 10 फीसद को अपनी वास्तविक आय में गिरावट झेलनी पड़ी है, जबकि शीर्ष 10 फीसद ने जबर्दस्त कमाई की है। आज पूर्ण-कालिक पुरुष मजदूर की मध्यमान वास्तविक आय, चार दशक पहले जितनी थी उससे कम है और सबसे नीचे की 90 फीसद आबादी की आय तीस वर्ष से ज्यादा से जहां की तहां बनी रही है। 25 उच्च आय अर्थव्यवस्थाओं में औसतन 65 से 70 फीसद तक परिवारों की वास्तविक आय, 2005 से 2014 के बीच या तो जहां की तहां रही है या उसमें गिरावट हुई है। गैलप पोल के अनुसार, 2000 में सिर्फ 33 फीसद अमरीकी खुद को मजदूर वर्ग का हिस्सा मानते थे। लेकिन, 2015 तक यह आंकड़ा 48 फीसद पर पहुंच चुका था यानी करीब आधी आबादी के बराबर।

वैश्विक आबादी के इस विशाल हिस्से की बदहाली और असमानता के ऐसे अश्लील रूप से ऊंचे स्तरों ने, बहुत भारी असंतोष पैदा किया है, जो किसी राजनीतिक अभिव्यक्ति की तलाश कर रहा है।

1.12 नवउदारवाद के इस संकट ने नये अंतर्विरोध पैदा किए हैं, जो साम्राज्यवादी देशों के बीच फटावों, टकरावों की ओर ले जा रहे हैं, जैसे ब्रेक्ज़िट। नयी राजनीतिक शक्तियों का उदय तथा बढ़ते तनाव आम बात हो गए हैं।

दक्षिणपंथ की ओर राजनीतिक झुकाव

1.13 21वीं कांग्रेस के बाद के दौर में दुनिया के अनेक देशों में दक्षिणपंथ की ओर राजनीतिक झुकाव और बढ़ा है। वर्तमान संकट के सामने, साम्राज्यवाद आक्रामक नवउदारवाद पर चल रहा है, जिसका योग एक वैश्विक विभाजनकारी एजेंडा के साथ हो रहा है, जो घरेलू, स्थानीय तथा क्षेत्रीय तनावों को पोस रहा है। यह नस्लवाद, पर-भीति और धुर-दक्षिणपंथी नवफासीवादी प्रवृत्तियों में बढ़ोतरी लाता है। अमरीकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत; ब्रिटेन में ब्रेक्ज़िट के मतदान में दक्षिणपंथ के पक्ष में गोलबंदी; फ्रांस में धुर दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट की मेरीन ला पेन की चुनावी बढ़त; जर्मनी में आल्टर्नेटिव फॉर डॉइशलैंड का आगे बढ़ना; आस्ट्रिया में दक्षिणपंथी सरकार का गठन जिसमें धुर दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी शामिल है; और योरपीय संसद के करीब एक-तिहाई सदस्यों का दक्षिणपंथी तथा अति-दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधि होना; दक्षिणपंथ की दिशा में इस झुकाव की ही अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रवृत्ति का भी भारत की राजनीति में प्रतिबिंबिन हो रहा है।

1.14 तीव्र वैश्विक आर्थिक संकट के इस दौर में, इस पर एक राजनीतिक लड़ाई सामने आ रही है कि बढ़ते जन असंतोष को कौन गोलबंद कर पाता है। राजनीतिक दक्षिणपंथ, जन असंतोष को गोलबंद करने के जरिए और यह सुनिश्चित करने के जरिए आगे बढ़ता है कि वामपंथी तथा प्रगतिशील शक्तियां एक बड़ी ताकत के रूप में सामने न आ सकें। जनता के असंतोष को भुनाने वाली ये दक्षिणपंथी ताकतें अंतत: ठीक उन्हीं आर्थिक नीतियों पर चलती हैं, जो इस आर्थिक संकट तक लायी हैं, जिसने जनता पर अभूतपूर्व बोझ लादा है और जिन नीतियों की वजह से ही जन असंतोष पैदा हुआ था। यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में दुनिया के अनेक देशों की राजनीतिक दिशा इससे तय हो रही होगी कि इस असंतोष को गोलबंद करने में राजनीतिक रूप से कौन कामयाब होता है, वामोन्मुख जनवादी

ताकतें या राजनीतिक दक्षिणपंथ। 1929-30 की महामंदी की पृष्ठभूमि में, विश्व की इजारेदार पूंजी के समर्थन से, फासीवाद का उदय हुआ था। फासीवादी ताकतें, संकट के चलते पैदा हुए बढ़ते हुए जन असंतोष का, सफलता से दोहन करने में कामयाब रही थीं। वर्तमान परिस्थिति संयोग के संदर्भ में लंबे आर्थिक संकट के खिलाफ बढ़ता जन असंतोष, घोर दक्षिणपंथी नव-फासी ताकतों के उभार के लिए ईंधन मुहैया करा रहा है।

1.15 **प्रति-संतुलनकारी रुझान:** बहरहाल, विभिन्न देशों में वामोन्मुख मंचों के उदय तथा उभार के जरिए, इस ज्वार को रोकने के लिए राजनीतिक संघर्षों के रूप में, प्रतिसंतुलनकारी घटनाविकास भी सामने आ रहे हैं।

1.16 फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चक्र में वामपंथी गठबंधन के उम्मीदवार, ज्यां लक मैलेंकोन को करीब 20 फीसद वोट मिले थे। चुनाव के अंतिम चरण में धुर दक्षिणपंथी पार्टी की हार हुई। बहरहाल, करीब एक-तिहाई मतदाताओं ने या तो मतदान ही नहीं किया या अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए और इस तरह एक नवउदारवादी बैंकर और एक फासीवादी के बीच से चुनाव करने से इंकार कर दिया। कुछ अन्य देशों में भी अति-दक्षिणपंथ के उभार के खिलाफ इस तरह का प्रतिरोध सामने आया है।

1.17 पुर्तगाल तथा ग्रीस जैसे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां—क्रमश: पीसीपी तथा केकेई—एक मजबूत ताकत बनी रही हैं और उन्होंने चुनावी बढ़त दर्ज करायी है। साइप्रस में कम्युनिस्ट पार्टी—एकेईएल—ने हाल के स्थानीय म्यूनिसिपल चुनावों में अपनी स्थिति पहले से बेहतर कर ली है।

1.18 योरप में अन्यत्र नव-वामपंथी संगठन उभर कर सामने आये हैं। ग्रीस में सिरिजा ने इसके वादे पर चुनाव जीता था कि नवउदारवादी सुधारों का मुकाबला किया जाएगा और मजदूर वर्ग पर हमलों को पलटा जाएगा तथा मेहनतकश जनता के कमजोर हुए जनतांत्रिक अधिकारों को बहाल किया जाएगा। लेकिन, अंतिम विश्लेषण में सिरिजा ने योरपीय वित्तीय पूंजी के दबाव के आगे घुटने टेक दिए और इसने धुर-दक्षिणपंथ के लिए और ज्यादा गुंजाइश बनाने का ही काम किया है। इसके चलते ग्रीस की जनता के बीच पैदा हुआ असंतोष, धुर दक्षिणपंथ के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई का मैदान है। स्पेन में एक प्रगतिशील पार्टी, पीओडीईएमओएस का गठन हुआ है और उसने वामपंथी ताकतों के साथ गठबंधन कर, खासा बड़ा चुनावी समर्थन हासिल किया है।

1.19 यूनाइटेड किंगडम में जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में लेबर पार्टी के पुनर्जीवन ने चुनाव अभियान में जनता के मुद्दों की केंद्रीयता को फिर से रेखांकित किया है और एक अर्थ में यूके में वामपंथी एजेंडे को पुनर्जीवित किया है। अमरीका में बर्नी सेंडर्स, मेहनतकश जनता के बीच अपने अभियान जारी रखे हुए हैं और उसका समर्थन जुटा रहे हैं।

1.20 इस दौर में योरप में सोशल डैमोक्रेटिक पार्टियां और हाशिए पर पड़ी हैं और अति-दक्षिणपंथ का उभार हुआ है। ग्रीस में पासोक, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, इटली की सोशलिस्ट पार्टी तथा जर्मन सोशल डैमोक्रेटिक पार्टी तथा इसके साथ ही अनेक स्कैंडिनेवियाई सोशल डैमोक्रेटिक पार्टियों, आदि सोशल डैमोक्रेटिक पार्टियों ने चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन किया है और गिरावट की स्थिति में हैं। इसकी वजह यह है कि इन पार्टियों ने मेहनतकश जनता के हितों के साथ विश्वासघात कर, नवउदारवाद को गले लगाया था। जनता द्वारा उनका इस तरह ठुकराया जाना जोरदार तरीके से सोशल डैमोक्रेसी के इस शास्त्रीय चरित्र का ही ठुकराया जाना है कि वह विपक्ष में रहते हुए मजदूर वर्ग की झंडाबरदार होती है और सरकार में रहते हुए, पूंजीपति वर्ग की।

1.21 ये घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जहां कहीं भी वामपंथी तथा वामोन्मुख शक्तियों ने जोरदार तरीके से नवउदारवाद तथा साम्राज्यवादी आक्रामकता के विरोध की झंडाबरदारी की है तथा जन गोलबंदी तथा संघर्षों को मजबूत किया है, उन्होंने सोशल डैमोक्रेटों को पीछे छोड़ दिया है, जन समर्थन हासिल किया है और प्रगति दर्ज करायी है। भविष्य में यह राजनीतिक लड़ाइयों का मैदान होने जा रहा है। नवउदारवाद के कारगर वामोन्मुखी प्रतिपक्ष के अभाव में, दक्षिणपंथ बढ़ते हुए जन असंतोष को भुना लेता है।

साम्राज्यवादी आक्रामकता

1.22 वैश्विक पूंजीवादी आर्थिक संकट ने, अमरीकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में बढ़ी हुई साम्राज्यवादी आक्रामकता के लिए पृष्ठभूमि मुहैया करायी है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, खासतौर पर मध्य एशिया/ उत्तरी अफ्रीका तथा लातीनी अमरीका में, अमरीकी सैन्य हस्तक्षेप या अमरीका-नीत नाटो के नेतृत्व में सैन्य हस्तक्षेप जारी हैं। अमरीका-इस्त्राइल गठजोड़ के हस्तक्षेप, मध्य-पूर्व के घटनाविकास को सख्ती से अपने शिकंजे में बनाए हुए हैं। नाटो ने अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया है और उसके सैन्य बलों ने इतिहास में पहली बार बाल्टिक देशों में तथा पोलैंड में

पांव रखे हैं। अमरीकी साम्राज्यवाद, 'चीन को घेरने' के अपने रणनीतिक लक्ष्य को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाना जारी रखे है। समाजवादी देशों के खिलाफ अमरीकी साम्राज्यवाद की आक्रामक कार्रवाइयों से, वर्तमान युग का केंद्रीय अंतर्विरोध—साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच अंतर्विरोध—तीखा हो रहा है।

1.23 **अमरीका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प:** अमरीका के राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रम्प का पहुंचना, अमरीकी सत्ताधारी वर्ग के सबसे प्रतिक्रियावादी हलकों की जीत को दिखाता है। यह इसका शास्त्रीय उदाहरण है कि किस तरह राजनीतिक दक्षिणपंथ ने जीत हासिल करने के लिए, अमरीकी मजदूर वर्ग के बीच जन असंतोष को भुनाया है। बहरहाल, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रम्प जोर-शोर से नवउदारवादी नीति पथ पर ही चल रहा है। उसने ईरान, फिलिस्तीन, क्यूबा तथा अफगानिस्तान के मामले में, पिछले अमरीकी प्रशासन द्वारा लिए गए अनेक कदमों को भी पलट दिया है। ट्रम्प ने वेनेजुएला तथा कोरियाई जनवादी गणराज्य के विरुद्ध उग्र रुख अपनाया है और इस तरह नये टकराव तथा तनाव खड़े किए हैं। इस्राइल तथा साऊदी अरब के लिए उसका हार्दिक समर्थन, अरब दुनिया में तनाव तथा टकराव बढ़ाना जारी रखे हुए है।

1.24 **बढ़ते सैन्य खर्चे:** वैश्विक आर्थिक संकट के चलते आयी खामोशी के बाद, सैन्य खर्चों ने एक बार फिर बढ़ना शुरू कर दिया है। आज अमरीका अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3.58 फीसद सैन्य खर्चों में लगा रहा है, जबकि इसका वैश्विक औसत, विश्व जीडीपी के 2.3 फीसद के बराबर है। 2018 के लिए अमरीका के रक्षा बजट में अभूतपूर्व रूप से 700 अरब डालर आवंटित किए गए हैं। नाटो के कुल सैन्य खर्चे में, जिसमें 70 फीसद खर्चा अकेले अमरीका का ही होता है, 2014 में 1.4 फीसद की गिरावट हुई थी, लेकिन 2015 में उसमें 1.8 फीसद की वृद्धि हुई और यह दर 2017 में और बढ़कर 4.3 फीसद पर पहुंच गयी।

1.25 साम्राज्यवाद द्वारा सैन्य खर्चों में इस तरह की बढ़ोतरी का मकसद सीधे-सीधे यही है कि अपना विश्व वर्चस्व कायम करने की अमरीका की मुहिम को और मजबूत किया जाए। हमने अपनी पिछली कांग्रेसों में यह दर्ज किया था कि लातीनी अमरीका, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सैन्य हस्तक्षेप जारी रखते हुए भी, अमरीका का वैश्विक रणनीतिक जोर अब, प्रशांत सागर की ओर मुड़ गया है। अब जबकि उसका दो-तिहाई नौसैनिक बेड़ा प्रशांत सागर में है, अमरीका खासतौर पर दक्षिण चीन सागर विवादों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि 'चीन को घेर सके' जिसे वह विश्व वर्चस्व के अपने मंसूबों के लिए एक

संभावित रूप से उभरते हुए प्रतिद्वंद्वी की तरह देखता है।

लातीनी अमरीका

1.25 लातीनी अमरीका में, अमरीकी साम्राज्यवाद के राजनीतिक तथा सैन्य हस्तक्षेपों में तेजी से बढ़ोतरी के बाद, वहां की जनता और अमरीकी साम्राज्यवाद के बीच एक तीखा टकराव पनप रहा है। समाजवादी क्यूबा उसके हमलों के केंद्र में बना हुआ है। ओबामा प्रशासन ने सुलह-समझौते के जो मामूली कदम उठाए थे उन्हें भी पलटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। अमरीकी साम्राज्यवाद वेनेजुएला को निशाना बना रहा है और उसने वहां खाने-पीने की चीजों की तंगी थोप दी है। इसी प्रकार ब्राजील व बोलीविया में तथा अन्य देशों में अमरीकी हस्तक्षेप तेजी से बढ़ रहे हैं ताकि लातीनी अमरीकी वामपंथ के उभार को रोका जा सके और इन देशों की अर्थव्यवस्था तथा राजनीति पर पहले अमरीका का जो नियंत्रण हुआ करता था, उसे बहाल किया जा सके। अमरीका, अर्जेंटीना में दक्षिणपंथी नवउदारवादी मोरीसियो माक्री को राष्ट्रपति पद पर चुनवाने में सफल रहा है। ब्राजील में एक संवैधानिक तख्तापलट में, देश की निर्वाचित राष्ट्रपति डिल्मा रूस्सोफ को भ्रष्टाचार के गढ़े हुए आरोपों में महाभियोग के जरिए हटा दिया गया। पूर्व-राष्ट्रपति लूला को भी, जिन्हें भारी जनसमर्थन हासिल है, ऐसे ही आरोप लगाकर नजरबंद कर दिया गया, ताकि वह आगामी चुनाव नहीं लड़ सकें। अमरीका-समर्थित दक्षिणपंथी ताकतों के खिलाफ, जो जनता कड़ी लड़ाइयों के बाद जीते गए जनतांत्रिक अधिकारों को पांवों तले रौंदने की कोशिश कर रही हैं, ब्राजील की जनता एक तीखे टकराव में भिड़ी हुई है।

1.27 15 अक्टूबर 2017 को वेनेजुएला में क्षेत्रीय गवर्नरों के लिए चुनाव हुए थे। अमरीका, बोलीवारीय क्रांति-विरोधी ताकतों के लिए अपनी तमाम आर्थिक सहायता के बल पर यह उम्मीद लगाए हुए था कि इन चुनावों में निकोलस मडुरो की सरकार को भारी धक्का लगेगा। अमरीका को उम्मीद थी कि यह 2018 के अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में, ह्यूगो चावेज की पार्टी, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला (पीएसयूवी) की हार के लिए जमीन तैयार कर देगा। लेकिन, पीएसयूवी ने आखिरकार गवर्नर के 23 पदों में से 18 जीत लिए। साफ है कि वेनेजुएला की जनता के बीच बोलीवारीय विकल्प के लिए समर्थन अब भी मजबूत बना हुआ है।

1.28 होंडूरास में 26 नवंबर 2017 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में फर्जीवाड़े के व्यापक पैमाने

पर आरोप लगने के बावजूद अमरीकी साम्राज्यवाद ने, राष्ट्रपति हर्नांदेज के पुनर्चुनाव को खुल्लमखुल्ला समर्थन दिया है। अमरीकी साम्राज्यवाद का होंडूरास तथा मध्य अमरीका के अन्य देशों में हस्तक्षेपों का लंबा इतिहास रहा है। 2009 में उसने होंडूरास में तख्तापलट कराया था ताकि वहां खनन तथा अति-सस्ते श्रम अड्डों में बहुराष्ट्रीय निगमों के भारी स्वार्थों की रखवाली की जा सके। इस चुनावी धांधली के खिलाफ फूटी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध कार्रवाइयों को नृशंसतापूर्वक कुचला गया है और एक दमनकारी निजाम कायम कर दिया गया है, जिसे अमरीकी साम्राज्यवाद का समर्थन हासिल है।

1.29 मध्य अमरीका के ही एक और देश निकारागुआ में, अपने लोकप्रिय कदमों के बल पर, जिनसे देश में गरीबी में करीब-करीब 13 फीसद अंक की कमी हुई है, दानियल ओर्तेगा दोबारा चुन लिए गए हैं। वेनेजुएला के अलावा लातीनी अमरीका में अन्यत्र बोलीविया, इक्वाडोर, होंडूरास तथा निकारागुआ में, अमरीकी साम्राज्यवाद सक्रिय है और इन वामपंथी-प्रगतिशील सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है।

पश्चिम एशिया

1.30 पश्चिम एशिया में अमरीका-इस्राइल धुरी अपनी केंद्रीय भूमिका जारी रखे हुए है, जिसका लक्ष्य है अमरीकी साम्राज्यवाद के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण और इस्राइल को सुदृढ़ करने, दोनों के लिए ईरान को कमजोर तथा अलग-थलग करना।

1.31 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पहली बार ऐसा प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद, जो फिलिस्तीन के पूर्वी यरूशलम तथा पश्चिमी तट के इलाकों अपनी अवैध बस्तियां बनाए रखने के लिए, इस्राइल की भर्त्सना करता है, इस्राइल ने बड़ी नंगई से इसकी योजनाएं बनायी हैं कि पूर्वी-यरूशलम में, जो फिलिस्तीनी राज्य की निर्दिष्ट राजधानी है, यहूदियों के लिए अवैध बस्तियां निर्मित की जाएं तथा उनका विस्तार किया जाए और हजारों नये घर बनवाए जाएं।

1.32 इस पृष्ठभूमि में, यरूशलम को इस्राइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने तथा अमरीकी दूतावास को तेल अबीव से वहां ले जाने का डोनाल्ड ट्रंप का फैसला एक खुल्लमखुल्ला उकसावे की कार्रवाई है, ताकि फिलिस्तीनी भूभाग पर इस्राइल के अवैध कब्जे को सही ठहराया जाए। यह कदम, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इस रुख से बिल्कुल उलट है कि पूर्वी

यरूशलम, 1967 से इस्राइल द्वारा हथिआया हुआ इलाका है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत रुख है कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य हो, जिसकी राजधानी पूर्वी-यरूशलम हो। इस तरह अमरीकी प्रशासन, इस्राइल तथा फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ताओं की किसी भी संभावना को विफल करने के लिए जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रम्प का यह फैसला इस क्षेत्र में और तनाव व टकराव भड़काएगा, जिसके वैश्विक परिणाम होंगे।

1.33 पश्चिम एशिया के अन्य इलाकों में अमरीकी हस्तक्षेप जारी हैं। रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किए जाने के बहाने से वह सीरिया पर मिसाइल हमले कर रहा है। बहरहाल, अब यह स्पष्ट हो गया है कि सीरिया में सत्ता बदल कराने की उसकी कोशिशें विफल हो गयी हैं। सात साल लंबे गृह युद्ध में सीरियाई बलों की प्रगति एक बड़ी उपलब्धि है जो सीरिया में सत्ता बदल कराने की अमरीकी साम्राज्यवाद की तमाम कोशिशों के खिलाफ जाती है। इस भीषण युद्ध में 4 लाख नागरिकों की जानें गयी हैं। अमरीका तथा उसके अरब सहयोगियों द्वारा समर्थित इस्लामवादी ताकतों के विफल होने का, पश्चिम एशिया की राजनीति पर गहरा असर पड़ने जा रहा है। सीरिया में रूस के रणनीतिक सैन्य हस्तक्षेप से, इस क्षेत्र में उसका प्रभाव सुदृढ़ हुआ है। रूस-तुर्की-ईरान संयुक्त पहल ने, इस क्षेत्र में अमरीकी मंसूबों को विफल किया है। अब जब अमरीका को सीरिया के असद निजाम को उखाड़ने का अपना लक्ष्य हासिल होना मुश्किल लग रहा है, वह इस क्षेत्र में अपना ध्यान ईरान की ओर मोड़ रहा है। ईरान इस क्षेत्र में अमरीकी रणनीति का मुख्य निशाना बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ नाभिकीय समझौते को प्रमाणित करने से इंकार कर दिया है, जो दिखाता है कि ईरान पर भी तथा इस क्षेत्र पर भी, दोनों पर नये दबाव लादे जाने वाले हैं।

1.34 साऊदी अरब को अपना सहयोगी बनाकर अमरीका, ईरान को कमजोर करने की कोशिश में, साऊदियों को इसके लिए बढ़ावा देता आया है कि यमन में अपना सैन्य हस्तक्षेप जारी रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है कि 2017 के दिसंबर के आखिर तक यमन में कम से कम 50 हजार बच्चों ने भूख तथा भुखमरी से दम तोड़ दिया होगा।

1.35 इसी बीच खुद साऊदी अरब में आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। साऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सत्ता में आने के साथ कतर, सीरिया तथा यमन में साऊदी अरब के हस्तक्षेप जारी हैं। वह अब लेबनान को निशाना बना रहा है ताकि हिज्बुल्ला को कमजोर किया जा सके।

1.36 **कतर:** कतर के अमीर को अलग-थलग करने तथा उसे कमजोर करने की साऊदी अरब तथा उसके सहयोगियों की कोशिशों को, शुरूआत में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन मिल रहा था। साऊदी अरब ने मांग की है कि कतर फौरन ईरान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध तोड़े, इलैक्ट्रोनिक मीडिया नैटवर्क ***अल जज़ीरा*** को निलंबित कर दे और हमास तथा मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े सभी लोगों को देश से निकाल दे। कतर तथा ईरान, दक्षिण फारस गैस फील्ड में साझीदार हैं, जो दुनिया भर में सबसे बड़ी गैस फील्ड है। इसके चलते दोनों के लिए हाइड्रो कार्बन के क्षेत्र में सहयोग करना जरूरी है। जहां साऊदी अरब तथा यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) कतर में सत्ता बदल कराना चाहते हैं, इस क्षेत्र में कतर के भी अपने सहयोगी हैं। लेकिन, इसके साथ ही अमरीका ने कतर को लड़ाकू विमान बेचने के 12 अरब डालर के सौदे पर भी दस्तखत किए हैं। इस क्षेत्र में अमरीका का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा भी कतर में ही है। इस अड्डे पर 10 हजार से ज्यादा अमरीकी सैनिक तैनात हैं। कतर में ही अमरीकी सेंटकॉम (सीईएनटीसीओएम) का अग्रिम मुख्यालय भी स्थित है। सीरिया तथा इराक में अमरीकी सैन्य कार्रवाइयों में सेंटकॉम की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।

अफ्रीका

1.37 उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र में धार्मिक तत्ववादी ताकतों का बोलबाला बना हुआ है। लीबिया पर हमले ने सिर्फ इस देश को ही अस्थिर नहीं किया था बल्कि इस समूचे क्षेत्र पर इसके गंभीर नतीजे दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक अतिवादी तथा आतंकवादी ताकतों की उपस्थिति बढ़ गयी है। आतंक का मुकाबला करने के नाम पर अमरीका, अफ्रीकॉम (एएफआरआइसीओएम) के जरिए अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर रहा है। नाइजीरिया, माली, साहेल क्षेत्र आदि कई देशों में तथाकथित आतंकविरोधी कार्रवाइयों में अमरीकी सैनिकों के मारे जाने की खबरें आयी हैं। अमरीका इन देशों के आंतरिक मामलों में इसीलिए हस्तक्षेप कर रहा है ताकि उनके समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर सके, महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों व बाजारों पर नियंत्रण कर सके और अफ्रीकी महाद्वीप में चीन के बढ़ते प्रभाव की रोक-थाम भी कर सके।

दक्षिणी अफ्रीका

1.38 दक्षिण अफ्रीका में देश के राष्ट्रपति तथा अफ्रीकी राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष, जैकब जूमा को अपने भ्रष्टाचार के अकाट्य साक्ष्य सामने आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा

है। उनके पद पर रहने से अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस-दक्षिण अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी-कोसाटू के त्रिपक्षीय गठबंधन की सुसंबद्धता के लिए खतरा पैदा हो गया था। बुजुर्ग ट्रेड यूनियन नेता सिरिल रामफोसा ने जूमा की जगह राष्ट्रपति का पद संभाला है। जिंबाब्वे में, 37 वर्ष तक आजाद जिंबाब्वे का सुप्रीम नेता रहने के बाद, राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। आगे चलकर, इम्मर्सन म्नानागवा को जैडएनयूपीएफ अध्यक्ष पद पर और 2018 में होने जा रहे अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुन लिया गया।

साम्राज्यवाद के आपसी अंतर्विरोध

1.39 सुदीर्घ पूंजीवादी संकट तथा नवीकृत साम्राज्यवादी आक्रामकता की पृष्ठभूमि में, साम्राज्यवादी खेमे की सुसंबद्धता पर प्रतिकूल असर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के नेतृत्व में साम्राज्यवादी विश्वीकरण की पृष्ठभूमि में, साम्राज्यवाद के आपसी अंतर्विरोधों के जिस मंद पड़ने को हमने अपनी पिछली कांग्रेसों में दर्ज किया था, उसमें बिखराव आ रहा है। ब्रैक्ज़िट के पक्ष में मतदान इसका एक उदाहरण है। डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों और योरपीय यूनियन तथा जापान जैसे अन्य पूंजीवादी केंद्रों के बीच खिंचाव तेज से तेज हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया है, जिसका झंडा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी ने उठा रखा था और यह फैसला जापान के हितों के खिलाफ गया है।

1.40 राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा अमरीका में इस्पात तथा एल्युमीनियम के आयातों पर बढ़े हुए तटकर लगाए जाने के बाद, चीन से आयातित अनेक मालों पर बढ़ा हुआ तटकर लगाया गया है। इससे व्यापार युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। अमरीका के इस तरह के संरक्षणवादी कदम अपने योरपीय सहयोगियों से भी उसका टकराव कराने जा रहे हैं।

1.41 पेरिस जलवायु संधि से अमरीका के हट जाने से अमरीका और योरपीय यूनियन के बीच टकराव तीखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प इसका आग्रह कर रहा है कि योरपीय सहयोगी नाटो गठबंधन के लिए वित्त जुटाने में कहीं ज्यादा हिस्सा डालें और यह भी बढ़ते तनावों का एक क्षेत्र है। पिछले ही दिनों डोनाल्ड ट्रम्प ईरान नाभिकीय समझौते से मुकर गया है और इसने एक ओर अमरीका तथा दूसरी ओर इस समझौते के अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं—जर्मनी, फ्रांस, रूस तथा यूके—के बीच टकरावों को तेज कर दिया है। अमरीका के योरपीय सहयोगियों के डोनाल्ड ट्रम्प

के इस कदम का अनुमोदन करने की कोई संभावना नहीं है। ये तमाम घटनाविकास इसी तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि साम्राज्यवादी विश्वीकरण के जरिए, मुनाफों का निर्माण अधिकतम करने के लिए, जनता का आर्थिक शोषण तेज करने के मामले में तो साम्राज्यवादी खेमा सुसंबद्ध तरीके से चल रहा हो सकता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में टकराव तथा अंतर्विरोध के बढ़ते मैदान सामने आ रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन

1.42 अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की इसकी घोषणा के साथ कि अमरीका, पेरिस समझौते का अनुमोदन नहीं करेगा, विश्व ताप में अनेक वर्षों से हो रही बढ़ोतरी के चलते पर्यावरण के नुकसान के रुझान को पलटने का संघर्ष एक बार फिर ठप्प पड़ गया है।

1.43 विकसित देशों द्वारा अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींचे जाने की आशंकाएं एक बार फिर सच साबित हुई हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए, 2016 के दिसंबर में जो पेरिस समझौता हुआ था, उसने एक गहराई तक असंतोषजनक व्यवस्था दी है जो न तो विज्ञान के तकाजे पूरे करती है और न विकसित तथा विकासशील देशों के बीच जड़ें जमाए बैठी नाबराबरी को संबोधित करती है। पेरिस समझौते का स्वैच्छिक वचनबद्धताओं का जो ढांचा है, इसका नतीजा यह है कि दुनिया विश्व ताप में 3 डिग्री सैल्शियस से ज्यादा की बढ़ोतरी की ओर लुढ़क रही है, जोकि सहमत हुए 2 डिग्री सैल्शियस के लक्ष्य से भी ज्यादा है, फिर 1.5 डिग्री सैल्शियस की महत्वाकांक्षी आकांक्षा के मुकाबले की तो बात ही क्या है?

1.44 अमरीका ने पेरिस समझौते को अपने मंसूबों के हिसाब से ढलवाया था। बजाय इसके कि विकसित देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी के बाध्यकारक लक्ष्य तय किए जाते, ताकि उन्हें पर्यावरण के वैश्विक नुकसान के लिए अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह बनाया जाता, अब सभी देशों को सिर्फ उत्सर्जन कटौती के स्वैच्छिक लक्ष्य पेश करने होंगे। पुन: पहले जो इसकी वचनबद्धताएं स्वीकार की गयी थीं कि विकसित देश, विकासशील देशों को वित्तीय मदद देंगे तथा उनके लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करेंगे, उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। अमरीका पर्यावरण परिवर्तन का ऐसा एजेंडा मनवाना चाहता है, जो मुख्यत: निजी पूंजी के स्वार्थों से नियंत्रित तथा संचालित है। पेरिस समझौता साफ तौर पर अपनी अतीत की हरकतों के लिए क्षतिपूर्ति करने की

विकसित दुनिया की हरेक जवाबदेही को ठुकराता है। हालांकि, विकासशील देश पेरिस समझौते में 'साझा किंतु भिन्नीकृत जिम्मेदारियों' के सिद्धांत का दोहराया जाना सुनिश्चित कर पाए हैं, लेकिन इस सिद्धांत को करीब-करीब नकार ही दिया गया है। अब, डोनाल्ड ट्रम्प के शासन में अमरीका एक बार फिर पेरिस समझौते से और इस तरह हरेक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नियंत्रण व्यवस्था से अलग हो गया है। यह इससे पहले क्योटो प्रोटोकाल से फिर जाने के अमरीका के रिकार्ड के अनुरूप ही है। वैसे भी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषणकर्ता होने के बावजूद अमरीका ने, उत्सर्जन में कटौती की नगण्य सी वचनबद्धताएं स्वीकार की थीं, जो उनके योरपीय समकक्षों के मुकाबले बहुत कम थीं।

1.45 भविष्य में होने वाली वार्ताओं में, खासतौर पर 2018 में होने वाले उत्सर्जन नियंत्रण प्रयासों के वैश्विक आकलन में, भारत को इससे सावधान रहना चाहिए कि विकासशील देश उस पर और गहरी कटौतियां करने के लिए दबाव डालने का प्रयास करेंगे। ये कटौतियां भारत के विकास के प्रयासों को गंभीरता से सीमित कर देंगी। जहां मौजूदा सरकार ने इस मामले में कोई प्रयास नहीं किए हैं, प्रगतिशील ताकतों को ऐसे कम कार्बन उत्सर्जन वाले कदमों के अपनाए जाने के लिए दबाव डालना चाहिए, जो गरीबों की तथा खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में गरीबों की बिजली, रसोई ईंधन तथा जन सार्वजनिक परिवहन समेत, आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच को बढ़ावा दें।

बहुध्रुवीयता

1.46 पिछली पार्टी कांग्रेस के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुध्रुवीयता के संबंध में परस्परविरोधी रुझान सामने आए हैं। भारत तथा ब्राजील में दक्षिणपंथी सरकारें हैं और दक्षिण अफ्रीका में एएनसी-कोसाटू-एसएसीपी गठबंधन कमजोर हुआ है, इस सब का ब्रिक्स के प्रभावीपन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। बहरहाल, ब्रिक्स ने सफलता के साथ शांघाई में एक नया विकास बैंक स्थापित किया है। पीछे जिन परस्परविरोधी घटनाविकासों का जिक्र किया गया है उनको देखते हुए, साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाओं की काट करने में इस बैंक के प्रभावीपन पर सवाल खड़े हो गए हैं।

1.47 शांघाई सहयोग संगठन ने एक असरदार क्षेत्रीय मंच के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ किया है और भारत तथा पाकिस्तान के पूर्ण सदस्यों के रूप में भर्ती किए जाने से उसका विस्तार हुआ है। चीन ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक

की स्थापना के लिए पहल की है, जिसके 60 सदस्य हैं, जिनमें कुछ विकासशील देश भी शामिल हैं।

1.48 इनमें से अनेक मंचों में, जिनको विकसित कर, एकध्रुवीयता के जरिए अपने वैश्विक वर्चस्व को सुदृढ़ करने की अमरीकी साम्राज्यवाद की मुहिम के खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुध्रुवीयता को मजबूत किया जा सकता है, भारत की भूमिका एक महत्वपूर्ण कारक बन गयी है। ऐसा विदेश, रक्षा तथा रणनीतिक रुखों में उसके मुखर अमरीकापरस्त बदलाव की वजह से हुआ है। भारत ने चीन की **वन बैल्ट, वन रोड** पहल में शामिल होने से इंकार कर दिया है। भारत का मौजूदा अमरीकी साम्राज्यवादपरस्त रुख, इन मंचों की जीवंतता तथा उनकी भावी संभावनाओं पर प्रतिकूल असर डालता रहेगा।

1.49 लातीनी अमरीका में अर्जेंटीना, ब्राजील आदि में दक्षिणपंथी सरकारें बनने और अन्य देशों में अमरीकी साम्राज्यवाद समर्थित दक्षिणपंथी हमले के चलते, अमरीकी सम्राज्यवादी एजेंडा की काट के तौर पर, यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन्स (उनासुर), मेरकाडो कॉमून डेल सूर (मर्कोसुर), बोलीवारियन एलाइन्स फॉर दी पीपुल्स ऑफ आवर अमेरिका (अल्बा) तथा कम्यूनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरीबियन स्टेट्स (सीईएलएसी) जैसे क्षेत्रीय मंचों की संभावनाएं कमजोर हुई हैं।

1.50 यूक्रेन को लेकर, एक ओर रूस तथा दूसरी ओर अमरीका तथा उसके पश्चिमी सहयोगियों के बीच टकराव, जो हमारी 21वीं कांग्रेस के समय तीखा हो रहा था, बना हुआ है। सीरिया में रूस ने अमरीका तथा उसके सहयोगियों को सफलता के साथ पछाड़ दिया है। रूस ने चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं और शांघाई कोआपरेशन, ब्रिक्स आदि बहुपक्षीय मंचों को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अमरीका जो एकध्रुवीयता चाहता है उसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ने के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है।

विश्व व्यापार संगठन वार्ताएं

1.51 जैसाकि पहले दर्ज किया जा चुका है, अमरीका तथा अन्य विकसित देश वार्ताओं के जरिए द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर व्यापार समझौते करने को ही तरजीह दे रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन अब वह मुख्य मंच नहीं रह गया है, जहां वैश्विक व्यापार नियम तय किए जाते हैं। अब जबकि 160 से ज्यादा देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हो गए हैं, अमरीका तथा अन्य विकसित देशों को ऐसी द्विपक्षीय

व क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के जरिए विकासशील देशों के प्रतिरोध को तोड़ना ही ज्यादा आसान लगता है।

1.52 भारत इस समय दो बड़े व्यापार समझौतों के लिए वार्ताएं कर रहा है—भारत-योरयीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौता और रीजनल कंप्रिहेंसिव इकॉनमिक पार्टनरशिप (आरसीइपी) जिसमें भारत के साथ 15 अन्य देश शामिल होंगे, जिनमें 10 आसियान देशों के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया तथा चीन शामिल होंगे। भारत-योरपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं पर गोपनीयता का पर्दा पड़ा हुआ है। जिन मुद्दों पर वार्ता हो रही है उनमें से कुछ भारतीय खेती, उससे जुड़ी गतिविधियों और सेवाओं के हितों के खिलाफ जाते हैं।

1.53 भाजपा सरकार के मुखर अमरीकापरस्त झुकाव के चलते, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी तथा अमरीकी हितों के सामने घुटने टेकने के विपरीत, अपने घरेलू हितों की हिफाजत करने के भारत के प्रयास, बढ़ते पैमाने पर बैठते जा रहे हैं। उक्त वार्ताएं अधिकतम गोपनीयता के साथ चलायी जा रही हैं और पहले जैसा होता था उसके विपरीत, जिन दस्तावेजों पर वार्ताएं हो रही हैं, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इन दस्तावेजों को संसद तक के सामने नहीं रखा जा रहा है। अन्य देशों से रिसकर इन दस्तावेजों के पाठ के बारे में जो जानकारियां आ रही हैं यही दिखाती हैं कि भारत अपने व्यापार नियम-कायदों को, विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अंतर्गत जो जरूरी था उससे कहीं आगे तक, और उदार बनाने के दबाव के सामने झुक रहा है। भारत के पेटेंट नियमों को ढीला कराने के दबाव खासतौर पर चिंता का कारण हैं, जिसका भारत में आने वाली दवाओं की कीमतों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसी तरह निवेश के नियमों को ढीला करने का दबाव भी चिंताजनक है, जो विदेशी कार्पोरेशनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की भारत सरकार की भूमिका को घटा रहा होगा, भले ही हमारे घरेलू हितों पर उनकी गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो।

1.54 2017 के आखिर में ब्यूनोस एअर्स में विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्रिस्तरीय बैठक हुई थी उसमें ई-कॉमर्स पर चर्चा हुई थी। यह ऐसा एजेंडा है जो विकसित देशों द्वारा थोपा जा रहा है ताकि ई-कॉमर्स की आड़ में व्यापार के नियमों को और ढीला कराया जा सके। ई-कॉमर्स की परिभाषा का विस्तार किया जा रहा है ताकि ऐसे तमाम व्यापार को इसके दायरे में लाया जा सके, जिसमें किसी भी तरह का इलैक्ट्रोनिक लेन-देन होता है। आज की दुनिया में लगभग सभी क्षेत्र इसके दायरे

में आ जाते हैं। विकसित देशों की मांग है कि ई-कॉमर्स को घरेलू करों से मुक्त किया जाना चाहिए। यह छोड़े जाने वाले तटकरों व अन्य शुल्कों के रूप में, भारत सरकार के राजस्व में भारी नुकसान की ओर ले जाएगा। इसका भारत के छोटे तथा मंझले उद्यमों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिन्हें भीमकाय वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ होड़ करनी पड़ेगी। अफ्रीकी देशों के समूह ने इस कदम का विरोध किया है, लेकिन भारत ने अब तक इस मामले में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।

1.55 इन वार्ताओं के क्रम में एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि भारत, जिसे विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों की नेतृत्वकारी आवाज माना जाता था, वैश्विक पूंजी के जूनियर पार्टनर की अपनी हैसियत को पुख्ता करने की कोशिश में, उस भूमिका को पहले ही छोड़ चुका है।

समाजवादी देश

1.56 **चीनः** पिछली कांग्रेस के बाद के दौर में चीन की अर्थव्यवस्था 7.2 फीसद की औसत सालाना दर से विस्तार करती रही है। उसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की अपनी हैसियत को बनाए रखा है। उसने वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 30 फीसद से ज्यादा का योगदान किया है। वैश्विक आर्थिक संकट से पैदा हुई कठिनाइयों पर काबू पाने के प्रयास में चीन ने एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया है कि उसने और ज्यादा घरेलू मांग तथा उपभोग पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए उसने लगातार न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है और 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कदम उठाए हैं। रोजगार में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है और हर साल औसतन 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा शहरी रोजगार पैदा किए गए हैं।

1.57 चीन की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। अनेक देश चीन की 'वन बैल्ट, वन रोड' परियोजना की पहल में शामिल हो गए हैं। यह पहल प्राचीन रेशम मार्ग और समुद्री मसाला व्यापार मार्ग को पुनर्जीवित करेगी। चीन द्वारा आगे बढ़ाये गए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी स्वागत हुआ है और पूरे 60 देश इसमें शामिल हो गए हैं, जिनमें यूके, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिण कोरिया जैसे, अमरीका के कुछ घनिष्ठतम सहयोगी भी शामिल हैं। शांघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स आदि कई बहुपक्षीय संगठनों की बढ़ी हुई ताकत चीन के बढ़ते पैमाने पर अपना जोर दिखाने का सबूत है। अंतर्राष्ट्रीय

संबंधों में चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित अमरीका ने, उसे घेरने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। वह दक्षिण चीन सागर, कोरियाई प्रायद्वीप तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। आने वाले दिनों में साम्राज्यवादी अमरीका और समाजवादी चीन के बीच तीखी होड़ देखने को मिलेगी।

1.58 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की हाल ही में संपन्न हुई 19वीं कांग्रेस ने, चीन के बढ़ते आत्मविश्वास तथा जोर को दिखाया है। कांग्रेस ने शी जिनपिंग को फिर से पार्टी का महासचिव चुना है और नये युग में चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद के निर्माण के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाने की एक रूपरेखा का अनुमोदन किया है। कांग्रेस ने दोहराया है कि यह नया युग, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधार पर आगे बढ़ेगा।

1.59 सीपीसी की कांग्रेस ने एक नयी अवधारणा पेश की है, 'एक नये युग के लिए चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर विचार।' कांग्रेस ने दोहराया है कि, 'नये युग में चीनी समाज के सामने खड़ा मुख्य अंतर्विरोध है, असंतुलित व अपर्याप्त विकास और एक बेहतर जिंदगी की जनता की लगातार बढ़ती जरूरतों के बीच का अंतर्विरोध। इसलिए, हमें विकास के अपने जनता केंद्रित दर्शन के लिए अपनी वचनबद्धता बनाए रखनी चाहिए और चौतरफा मानव विकास को तथा सभी के लिए साझा खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए।'

1.60 कांग्रेस ने तय किया कि सुधार तथा द्वार खोलने के अपने रास्ते पर चलना जारी रखा जाए और इसके साथ ही साथ असंतुलित तथा अपर्याप्त विकास से पैदा हुई तीव्र समस्याओं से दो-चार हुआ जाए तथा विकास की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस दौर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जोरों से भ्रष्टाचार का मुकाबला किया है और कुछ शीर्षस्थ नेताओं तक को नहीं बख्शा है, जिन्हें पकड़ा गया है और सजा दी गयी है। पार्टी कांग्रेस ने तय किया है कि इस संघर्ष को जारी रखा जाए और ऐसी बुराइयों से पूरी तरह से स्वच्छ करने के जरिए पार्टी को और मजबूत किया जाए।

1.61 **वियतनामः** वियतनाम इस क्षेत्र के तेजी से विकास करते देशों में से एक बना रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था इस दौर में औसतन 6.3 फीसद की दर से आगे बढ़ी है। इसके बावजूद, विश्व आर्थिक संकट के चलते यह देश खुद अपने तय किए गए कुछ लक्ष्य हासिल करने में विफल रहा है, जैसे 2020 तक एक आधुनिक औद्योगीकृत देश बनना। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की 12वीं कांग्रेस में, दोइ

मोइ (नवीकरण) की नीति पर चलना जारी रखने का फैसला लिया गया था, जो देश को औद्योगीकरण के रास्ते पर लेकर गयी है। इस कांग्रेस का यह निष्कर्ष था कि, 'यह जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा समाजवाद के लक्ष्य पर सुदृढ़ रहते हुए, मार्क्सवाद-लेनिनवाद तथा हो ची मिन्ह विचार का रचनात्मक तरीके से व्यवहार करते हुए तथा उनका विकास करते हुए, सोचने के तरीकों में जोर-शोर से नयी खोज करते रहा जाए।'

1.62 वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की 12वीं कांग्रेस ने, नवीकरण की नीतियों पर अमल के दौरान आयी कुछ कठिनाइयों और चुनौतियों की पहचान की थी। हालांकि, इस दौर में जनता की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, वियतनाम को शहरों और दूर-दराज के भीतरी इलाकों के बीच बढ़ती असमानताओं तथा अंतरों का भी मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस ने तय किया था कि पार्टी को मजबूत करने और मार्क्सवाद-लेनिनवाद तथा हो ची मिन्ह विचार को, वियतनामी सचाइयों के अनुरूप, रचनात्मक तरीके से लागू करने के जरिए, इन मुद्दों का सामना किया जाए।

1.63 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी ने हाल के दौर में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान किया है और दोनों देशों के बीच के विवाद के मुद्दों को वार्ताओं के जरिए हल करने का फैसला लिया है। यह एक सकारात्मक घटनाविकास है और इससे दोनों देशों के बीच और दक्षिण चीन सागर के पास-पड़ौस में भी, तनाव कम करने में मदद मिलेगी।

1.64 **क्यूबा:** क्यूबा की अर्थव्यवस्था, अमरीका द्वारा थोपी गयी अन्यायपूर्ण तथा अमानवीय आर्थिक नाकेबंदी की मार अब भी झेल रही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल करने के लिए ओबामा प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों में से अनेक को पलटने का और आर्थिक नाकेबंदी को और तीखा करने का रास्ता पकड़ा है। वेनेजुएला जैसे अनेक लातीनी अमरीकी देशों को जिन आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर उनका भी असर पड़ रहा है। समुद्री तूफानों जैसी प्राकृतिक आपदाओं का बार-बार शिकार बनना भी, क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डाल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में क्यूबाई शासन तथा क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सफलता के साथ एक पीढ़ीगत सत्ता हस्तांतरण किया गया है। राउल कास्त्रो राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हो गए और मिगुएल डियाज कनेल ने यह जिम्मेदारी संभाल ली, जो अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकख्यात नेता, फिदेल कास्त्रो का निधन भी इसी दौर में हुआ था। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद, क्यूबा की जनता पार्टी

के पीछे गोलबंद हुई है और उसने समाजवादी व्यवस्था की हिफाजत करने की तथा अस्थिरता पैदा करने की तमाम साम्राज्यवादी कोशिशों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने की कसम खाई है।

1.65 क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी की 7वीं कांग्रेस ने कुछ दस्तावेजों पर बहस कर उन्हें स्वीकार किया था, जिनमें क्यूबा में समाजवादी निर्माण तथा आर्थिक विकास के रास्ते का विवरण दिया गया है। ये दस्तावेज भविष्य का और एक संपन्न तथा वहनीय समाजवादी समाज के निर्माण का रास्ता तय करेंगे। इस कांग्रेस ने यह भी तय किया था कि नवउदारवादी नीतियों को, जो राजकीय संपत्ति और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं के निजीकरण को बढ़ावा देती हैं, क्यूबाई समाजवाद के अंतर्गत कभी भी नहीं अपनाया जाएगा। उसने यह भी दोहराया है कि उत्पादन के बुनियादी साधनों पर समूची जनता का स्वामित्व, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप बना रहेगा।

1.66 **कोरियाई जनवादी गणराज्य:** अमरीका की धमकियों की अवज्ञा कर, कोरियाई जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) ने अपने मिसाइल विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है और एक लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलेस्टिक मिसाइल का विकास किया है। इसके लिए डीपीआरके का तर्क यह है कि उसके लिए यही अमरीका के किसी सैन्य हमले से अपना बचाव करने की एकमात्र पक्की गारंटी है। अमरीका, कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाने में लगा रहा है और दक्षिण कोरिया के साथ, नाभिकीय हथियारों से लैस होकर, नियमित रूप से अपने सैन्य अभ्यास करता रहा है। पहले अमरीका ने दक्षिण कोरिया में थाड नाभिकीय मिसाइल प्रणाली लगायी थी और कोरियाई प्रायद्वीप का सैन्यीकरण और बढ़ा दिया है। डीपीआरके सीधे इसके निशाने पर है और इससे चीनी लोक जनवादी गणाराज्य के लिए भी खतरा पैदा होता है।

1.67 डीपीआरके पर थोपी गयी पाबंदियों ने आधी सदी से ज्यादा से उसे खाने-पीने की चीजों तथा अपनी जनता के लिए आवश्यकता की अन्य चीजों के बदले में, अपने समृद्ध खनिज संसाधनों का व्यापार करने से वंचित रखा है। इन परिस्थितियों में, अमरीका-दक्षिण कोरिया सैन्य धुरी से वर्तमान खतरे से अपनी हिफाजत करने के लिए, डीपीआरके अपनी रक्षा तैयारियों को पुख्ता करने पर, बहुत भारी संसाधन खर्च करता रहा है। बहरहाल, हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग के लिए नयी पहलें की गयी हैं। हाल ही में विंटर आलंपिक खेलों में एक संयुक्त कोरियाई दल का भाग लेना, उत्तर तथा दक्षिण के बीच के रिश्तों की जमी हुई बर्फ

के एक स्वागतयोग्य पिघलाव को दिखा रहा था। दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक खेलों में उत्तरी कोरियाई दस्ते की हिस्सेदारी, संबंधों में कुछ गरमाहट को दिखाती है और उसके बाद 27 अप्रैल 2018 को दोनों देशों के नेताओं की शिखर बैठक हुई है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने इशारा किया कि है कि वह आने वाले दिनों में कोरियाई जनवादी गणराज्य के नेता, किम जोंग उन के साथ मुलाकात कर सकते हैं।

1.68 **लाओस:** लाओस की आर्थिक वृद्धि की दर एशिया में सब से ऊंची दरों में से रही है। पिछले दशक के अधिकांश हिस्से में यह दर औसतन 7 फीसद से ऊपर रही है। लाओस ने अच्छी प्रगति की है और गरीबी घटाकर कर आधी कर ली है। उसने भूख कम की है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तरों में सुधार किया है। कृषि में वृद्धि से, जिसमें देश की श्रम शक्ति के 73 फीसद से ज्यादा को रोजगार मिलता है और श्रम सघन विनिर्माण के हाल में हुए विस्तार से, गरीबी को और कम करने में मदद मिलने की उम्मीद की जाती है।

हमारा पड़ौस

1.69 **पाकिस्तान:** इस्लामी तत्ववादियों और पाकिस्तान की जनता के बीच लड़ाई जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी हमले हुए हैं और निर्दोष लोगों की जानें गयी हैं। ओबामा के अफगानिस्तान से अमरीका की फौजें हटाने के एलान के बाद से, तत्ववादी ताकतों के काम-काज के लिए और जटिल स्थिति पैदा हुई थी। बहरहाल, अब जबकि डोनाल्ड ट्रम्प ने वहां अमरीकी फौजों की तैनाती बढ़ाने का फैसला कर लिया है, छलक कर इसका पाकिस्तान पर क्या असर होता है, यह देखने वाली बात होगी। हाल ही में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी गुहार लगायी थी कि अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में बातचीत के जरिए कोई निपटारा होना चाहिए।

1.70 पनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति नवाज शरीफ के इस्तीफा देने के बाद से, राजनीतिक रूप से सेना का बोलबाला और बढ़ गया है। जहां अमरीका, चीन पर अंकुश लगाने की अपनी नीति में एक कहीं पुख्ता सहयोगी के रूप में, इच्छुक भारत को लपेटने की अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, वहीं वह जब-तब की जाने वाली कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद, हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे हुए है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में और गिरावट आयी है। 2016 की **सर्जिकल स्ट्राइक्स** के

फलस्वरूप आतंकवादी हमलों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आयी है। हालांकि, दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों की तीसरे देशों में मुलाकातों की खबरें हैं, दोनों देशों के बीच सभी स्तरों पर बातचीत आधिकारिक रूप से बंद है और दोनों के बीच के रिश्तों में सुधार की ओर कोई रास्ता खुलने के आसार फौरन तो क्षितिज पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार का कठोर पाकिस्तानविरोधी रुख, भाजपा-आरएसएस के हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद लिए तथा भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ाने के लिए हथियार जुटाने का भी काम करता है, ताकि वे देश में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकें।

1.71 **बांग्लादेश:** अब जबकि बांग्लादेश के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस देश में तत्ववादी हमलों की लहर बाढ़ पर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, 2017 के शुरू में एक सरकारी यात्रा पर भारत आयी थीं। हालांकि, दोनों देश इस यात्रा की सफलता का दावा करते हैं, तीस्ता नदी के जल के बंटवारे के उलझे हुए मुद्दे पर समझौता, अब भी पहुंच से दूर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इससे पहले यूपीए सरकार और शेख हसीना सरकार के बीच समझौते के मसौदे का सार्वजनिक रूप से विरोध किया था। भाजपा की केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठाए हैं। भारतीय नागरिकता कानून में भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन भी दोनों देशों के बीच खिंचाव का बिंदु बन गए हैं। ये संशोधन भारत में आए हिंदू शरणार्थियों को तो करीब-करीब नागरिकता दे देते हैं, जबकि अन्य धर्मों शरणार्थियों के लिए इसकी मनाही कर देते हैं। भारत में हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता, बांग्लादेश में भी मुस्लिम तत्ववाद को मजबूत करती है। 2018 में होने वाले आम चुनाव में इन सभी मुद्दों के बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाएं भड़काने की ही संभावना है। इसका हमारे बिरादराना रिश्तों पर और ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

1.72 रोहिंग्या संकट तथा उसके चलते बांग्लादेश में शरणार्थियों की भारी बाढ़ के मुद्दे पर म्यांमार के साथ मध्यस्थता करने के बांग्लादेश के अनुरोध के प्रति, भारत का रुख उत्साहहीन बना रहा है। इस मानवतावादी संकट के समाधान के लिए, हाल ही में चीन ने तीन चरणों का एक कार्यक्रम पेश किया है: (अ) युद्ध विराम कराया जाए (जो अब लागू है); (ब) म्यांमार और बांग्लादेश, दोनों संवाद की लाइनें खुली रखें और शरणार्थियों की स्वदेश वापसी पर एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ताएं जारी रखें; और (स) रेखाइन प्रांत का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, जो कि झगड़े की असली जड़ है, एक दूरगामी समाधान निकाला जाए। चीनी

विदेश मंत्री द्वारा हाल की अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान पेश की गयी इस चीनी पहल का बांग्लादेश ने स्वागत किया है। बांग्लादेश पहले ही 'वन बैल्ट, वन रोड' पहल में शामिल हो चुका है और उसने पहली बार दक्षिण एशिया में दो देशों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए, चीन की कूटनीतिक पहल का स्वागत किया है।

1.73 **नेपाल:** राजनीतिक अस्थिरताओं और जल्दी-जल्दी सरकारों के बदलने के एक लंबे अर्से के बाद, नेपाल में अंतत: संविधान को लागू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत ही 2017 के नवंबर में वहां चुनाव हुए थे।

1.74 नेपाल में हाल ही में हुआ एक महत्वपूर्ण घटनाविकास, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एमसी) का चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन करने का फैसला था। दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनायी है और सीपीएन (यूएमएल) से के पी ओली, प्रधानमंत्री बने हैं। यह एक स्वागतयोग्य घटनाविकास है। इस कम्युनिस्ट गठबंधन ने इस बार के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है और संघीय संसद में करीब दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है। कम्युनिस्ट गठबंधन ने, सात प्रांतीय विधानसभाओं में से भी छ: में बहुमत हासिल किया है। चुनाव के ये नतीजे एक नयी शुरूआत के सूचक हैं, जो नेपाल में राजनीतिक स्थिरता का दौर लाएंगे। नेपाल के गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक चरित्र को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रगति का न सिर्फ नेपाल में बल्कि समूचे दक्षिण एशिया में भी, स्थिरता तथा शांति पर दूरगामी असर पड़ेगा। सीपीएन (यूएमएल) तथा सीपीएन (एमसी) ने इसका एलान किया है कि वे जल्द ही विलय कर एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगी। यह एक महत्वपूर्ण घटनाविकास है।

1.75 **श्रीलंका:** श्रीलंका में एसएलएफपी तथा यूएनपी की गठबंधन सरकार इस समय संविधान के एक नये मसौदे पर काम कर रही है, जिसका वांछित लक्ष्य है लंबे समय से चले आ रहे तमिल प्रश्न के राजनीतिक निपटारे का प्रावधान करना और एकीकृत श्रीलंका के हित में, तमिलभाषी क्षेत्रों को अधिकतम स्वायत्तता देना। यह उम्मीद की जाती है कि ये प्रयास कामयाब होंगे। हाल ही में मुसलमानों पर बौद्ध कट्टरपंथियों के जो हमले हुए हैं, श्रीलंकाई समाज में विभिन्न समुदायों के बीच मौजूद, पर्दे के पीछे से झांकते तनावों को ही रेखांकित करता है। हाल ही में संपन्न स्थानीय निकाय चुनावों में यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) तथा यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम एलांइस (यूपीएफए) के सत्ताधारी गठबंधन को, महिदा राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पोडुजना पेरमुना (एसएलपीपी) के हाथों हार का मुंह देखना

पड़ा है।

1.76 **भूटान:** डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच हाल ही में पैदा हुआ गतिरोध अंतत: हल हो गया और दोनों पक्षों ने अपनी जीत के दावे किए हैं। यह विवाद, ऐसे इलाके के गिर्द केंद्रित है जिस पर भूटान और चीन का दावा है, हालांकि भूटान ने इस मामले में करीब-करीब तटस्थ रुख अपनाया था। भूटान ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ दुहरे कराधान से बचने के समझौते पर दस्तखत किए हैं। भूटान, भारत के अलावा सार्क का ऐसा अकेला देश है जो 'वन बैल्ट, वन रोड' पहल में शामिल नहीं हुआ है। अब जबकि दूसरे सभी देश इस पहल में शामिल हो गए हैं और ओबीओआर के क्रम में ढांचागत विकास में बहुत बड़े पैमाने पर चीनी संसाधनों के आने की उम्मीद कर रहे हैं, इस पर भारत का कड़ा विरोध, भविष्य में पड़ौसियों के साथ हमारे संबंधों को जटिल बनाने जा रहा है।

1.77 **मालदीव:** मालदीव में गंभीर घटनाएं घट रही हैं। मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने, निर्वासित पूर्व-राष्ट्रपति की रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने उन्हें 2015 के मामले में लगाए गए आतंकवाद के सभी आरोपों से बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 पूर्व सांसदों की संसद की सदस्यता बहाल करने का भी आदेश दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति, अब्दुल्ला यामीन ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करने से इंकार कर दिया है और देश में इमर्जेंसी की घोषणा कर दी है। सार्क के एक देश के इस घटनाविकास पर नजदीकी नजर रखनी होगी।

कम्युनिस्ट एकजुटता

1.78 कम्युनिस्ट और वर्कर्स पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक हर साल हो रही है। महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति की शताब्दी मनाने के लिए 2017 में रूस में हुआ आयोजन, इस दौर में खास रहा। अनेक देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में बढ़ती हुई लोकप्रिय विरोध कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। जैसाकि पहले दर्ज किया जा चुका है, जब तक कम्युनिस्ट पार्टियों तथा वामपंथी पार्टियों द्वारा जनता के बढ़ते असंतोष को संगठित करने तथा पूंजी के शासन के खिलाफ मजदूर वर्ग के नेतृत्व में हमला बोलने के लिए वर्ग संघर्ष को तेज करने के जरिए, पूंजीवाद के राजनीतिक विकल्प को मजबूत नहीं किया जाता है, साम्राज्यवादी विश्वीकरण द्वारा थोपे गए इस निर्मम शोषण को खत्म नहीं किया जा सकता है।

1.78 अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन का एक दस्ता होने के नाते सी पी आइ (एम) को, भारत में खुद को मजबूत करने के जरिए और इस हमले की आर्थिक, राजनीतिक

तथा अन्य अभिव्यक्तियों के खिलाफ भारतीय जनता के लोकप्रिय संघर्षों को व्यापक बनाने तथा मजबूत करने की अपनी सामर्थ्य में भारी बढ़ोतरी करने के जरिए, इस वैश्विक संघर्ष में अपना योगदान करना होगा।

साम्राज्यवादविरोधी एकजुटता को मजबूत करो

1.80 सी पी आइ (एम), अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने भाजपा सरकार के पूर्ण समर्पण के खिलाफ और भारत को अमरीकी साम्राज्यवाद का अधीनस्थ रणनीतिक सहयोगी बनने के दर्जे में पहुंचाए जाने के खिलाफ, भारतीय जनता के बीच जोरदार अभियान चलाएगी। आर्थिक, रणनीतिक, प्रतिरक्षा तथा विदेश नीति, सभी क्षेत्रों में इस अधीनस्थ दर्जे की अभिव्यक्तियों का सी पी आइ (एम) विरोध करेगी।

1.81 सी पी आइ (एम), इस्त्राइली कब्जे के खिलाफ और अपने होमलैंड की जिस मांग से फिलिस्तीनी जनता को लंबे अर्से से वंचित रखा गया है, उसे हासिल करने के लिए, फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष के लिए अपना पूर्ण समर्थन बनाए हुए है।

1.82 सी पी आइ (एम), मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे बढ़ते हुए अमरीका-इस्त्राइल-भारत गठजोड़ का जोरों से विरोध करेगी।

1.83 सी पी आइ (एम), अलग-अलग ग्रुपों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद या राज्य प्रायोजित आतंकवाद, आतंकवाद के सभी रूपों तथा किस्मों का मजबूती से विरोध करना जारी रखे हुए है।

1.84 सी पी आइ (एम), समाजवादी चीन, वियतनाम, डीपीआरके, क्यूबा तथा लाओस के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती है और अपने-अपने देश में समाजवाद को मजबूत करने के उनके प्रयासों को अपना पूर्ण समर्थन देती है।

1.85 सी पी आइ (एम), नव-फासीवादी ताकतों के खिलाफ, तत्ववाद के खिलाफ, धार्मिक कट्टरता, पोंगापंथ के खिलाफ तथा प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ लड़ रही सभी ताकतों के साथ अपनी एकजुटता जताती है।

1.86 सी पी आइ (एम) दुनिया भर में और खासतौर पर दक्षिण एशिया व लातीनी अमरीका में, वामपंथी क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करेगी।

1.87 सी पी आइ (एम), तरह-तरह से साम्राज्यवाद द्वारा निशाना बनाए जा रहे समाजवादी देशों के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता जताती है।

1.88 वैश्विक स्तर पर सी पी आइ (एम) जहां नवउदारवाद के खिलाफ, अमरीकी सैन्य हस्तक्षेपों तथा हमलों के खिलाफ साम्राज्यवादविरोधी आंदोलनों की सभी अभिव्यक्तियों के साथ, और पर्यावरण व जलवायु के खतरनाक ढंग से बिगाड़े जाने के खिलाफ तथा सार्वभौम जलवायु न्याय के लिए संघर्ष की सभी अभिव्यक्तियों के साथ एकजुटता जतायेगी तथा सहयोग करेगी, वहीं इन अलग-अलग धाराओं को एकजुट करने का प्रयास करेगी ताकि दुनिया में एक ताकतवर, सर्वसमावेशी साम्राज्यवादविरोधी आंदोलन खड़ा किया जा सके।

राष्ट्रीय परिस्थिति

2.1 मोदी सरकार के करीब चार साल एक दक्षिणपंथी, तानाशाहीपूर्ण-सांप्रदायिक निजाम ले आए हैं। इस निजाम की विशेषताएं हैं: नवउदारवादी नीतियों पर और तेजी से चला जाना, जिसके चलते मेहनतकश जनता पर चौतरफा हमले हो रहे हैं; आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडा को लागू करने का सतत प्रयास, जिससे शासन के धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा पैदा हो गया है, अल्पसंख्यकों व दलितों पर हमले हो रहे हैं तथा फासीवादी रुझान सामने आ रहे हैं; अमरीका के साथ रणनीतिक गठजोड़ को मजबूत करना तथा एक अधीनस्थ सहयोगी की भूमिका अदा करना; और संसदीय जनतंत्र को कतरने तथा संवैधानिक संस्थाओं व जनतांत्रिक अधिकारों को ध्वस्त करने के जरिए, तानाशाही का ढांचा खड़ा करना।

2.2 पार्टी की 21वीं कांग्रेस में राजनीतिक परिस्थिति का आकलन इस प्रकार किया गया था:

''मई 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से राजनीतिक परिस्थिति में नाटकीय बदलाव आया है। पहली बार भाजपा को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है, हालांकि उसे डाले गए कुल वोटों का 31 फीसद ही हासिल हुआ है। इसने एक दक्षिणपंथी हमले के लिए मंच सजा दिया है, जिसमें नवउदारवादी नीतियों का हमलावर तरीके से आगे बढ़ाया जाना और आर एस एस के नेतृत्व में हिंदुत्ववादी ताकतों का अपने सांप्रदायिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए खुलकर प्रयास करना शामिल हैं। इस तरह का परिस्थिति संयोग, बढ़ती तानाशाही की पूर्व-सूचना देता है।''(पैरा 2.1)

2.3 प्रस्ताव में हालात की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं को भी दर्ज किया गया था:

(1) ''भाजपा सरकार के ग्यारह महीनों के दौर की पहचान नवउदारवादी नीतियों के आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाए जाने से होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को बढ़ाए जाने पर जोर है। इस दौर में निजीकरण बढ़ा है। इस दौर में श्रम कानूनों तथा भूमि अधिग्रहण कानूनों को कमजोर किया गया है।''

(2) ''जनता के खिलाफ यह चौतरफा हमला मौजूदा मुकाम पर तानाशाही को

सत्ताधारी वर्ग के लिए एक अनिवार्यता बना देता है।''

(3) ''भाजपा के सत्ता में आने और आर एस एस की कार्ययोजना के लागू किए जाने से, हालात में गुणात्मक बदलाव आया है।''

(4) ''विघटनकारी हिंदुत्व परियोजना को आगे बढ़ाने की चौतरफा कोशिश सामने आ रही हैं, जिससे हमारे गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष-जनतांत्रिक आधार के लिए ही खतरा पैदा हो रहा है।''

(5) ''मोदी सरकार अमरीका के साथ रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने को तेज कर रही है।''

(6) ''बढ़ते तानाशाहीपूर्ण रुझान जनतांत्रिक अधिकारों के गंभीर अतिक्रमण और नागरिक स्वाधीनताओं पर हमलों में प्रतिबिंबत हो रहे हैं।''

वर्तमान परिस्थिति

2.4 पार्टी कांग्रेस के बाद गुजरे तीन वर्षों ने इस विश्लेषण तथा राजनीतिक परिस्थिति की समझ के सही होने की पूरी तरह से पुष्टि की है। बाद के दौर में जो सामने आया है, वह है दक्षिणपंथी हमले के सभी घटकों का और तीखा होना।

आर्थिक स्थिति

2.5 पिछले चार साल के दौरान मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि, सरकार ने आंकड़ों की हेरा-फेरी से आर्थिक सुस्ती को छुपाने की तमाम कोशिशें की थीं, सचाई सामने आ ही गयी। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की श्रृंखला में संशोधन किया गया था ताकि उसकी बेहतर तस्वीर पेश की जा सके, फिर भी संशोधित जीडीपी श्रृंखला के हिसाब से भी वृद्धि दर लगातार गिरी है और 2015-16 के 8 फीसद से, 2017-18 के लिए 6.5 फीसद के अनुमान पर पहुंच गयी है। यह चार साल की सबसे कम वृद्धि दर है। लेबर ब्यूरो के आंकड़े दिखाते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहली बार कुल रोजगार का स्तर, 2013-14 और 2016-17 के बीच नीचे खिसका है।

2.6 आर्थिक मंदी, अर्थव्यवस्था के कुंजीभूत क्षेत्रों में और खासतौर पर अनौपचारिक क्षेत्रों में सबसे तीखी रही है। मोदी सरकार के पहले तीन साल के दौरान कृषि के जीडीपी में सिर्फ लगभग 1.7 फीसद सालाना की बढ़ोतरी हुई थी। खेती की

आमदनियां गिरी हैं क्योंकि उसके लिए सार्वजनिक खर्च में कटौतियां की गयी हैं, समर्थन मूल्य की गति धीमी हुई है, सार्वजनिक खरीद में कमी हुई है और लागत सामग्री की व्यवस्था के बढ़ते निजीकरण तथा कुछ महत्वपूर्ण लागत सामग्रियों पर ऊंचे अप्रत्यक्ष कर लगने के चलते, उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। फसल बीमा को निजी बीमा कंपनियों के लिए उपहार में तब्दील कर दिया गया है, जबकि किसान व्यापक पैमाने पर फसल के नुकसान से राहत से वंचित ही बने हुए हैं।

2.7 विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि के अलग-अलग स्रोतों पर आधारित अनुमान, परस्परविरोधी रुझान दिखाते हैं। इससे इस व्यापक रूप से फैले हुए संदेह को ही बल मिलता है कि इन आंकड़ों के साथ हेर-फेर की जा रही है ताकि अर्थव्यवस्था की कहीं ज्यादा आकर्षक तस्वीर पेश की जा सके। अल्पावधि के सरकारी आंकड़े अनौपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में हुए बदलावों को पकड़ नहीं पाते हैं। उद्योग का यही क्षेत्र है जिस पर नोटबंदी और जीएसटी के लागू किए जाने की सबसे बुरी मार पड़ी है। फिर भी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) जैसे सूचकांक भी दिखाते हैं कि अलग-अलग वर्षों में चंद औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश केंद्रीय महत्व के उद्योगों में तीन वर्षों में वृद्धि सुस्त बनी रही है। इस दौर में निर्यातों में निरंतर गिरावट दर्ज हुई है।

2.8 बैंकिंग क्षेत्र डुबाऊ कर्जों में भारी बढ़ोतरी के बोझ नीचे दबा हुआ है। चूंकि बैंकों को कार्पोरेट डिफाल्टरों के साथ नरमी दिखाने के लिए मजबूर किया गया है, कुल डुबाऊ कर्जे 2014 के दिसंबर के 2.6 लाख करोड़ के स्तर से बढ़कर, 2017 के सितंबर में 8.37 लाख करोड़ रु0 के स्तर पर पहुंच चुके थे। जहां नोटबंदी ने बैंकों पर जमाओं की भारी मात्रा का बोझ लाद दिया, वहीं ऋण की मांग सुस्त रहने का नतीजा यह हुआ है कि उनसे कम ऋण उठाए गए हैं। इन जमाओं पर ब्याज के बोझ ने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभकरता को और कमजोर कर दिया है।

2.9 हालांकि, अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के मामले में ऐसे अलग-अलग खास कारक रहे हैं, जिन्होंने आर्थिक मंदी में योग दिया है। फिर भी नोटबंदी और जीएसटी व्यवस्था का लागू किया जाना, ऐसी नीतिगत पहलों में प्रमुख हैं, जिनकी सत्यानाशी मार सभी प्रमुख क्षेत्रों पर पड़ी है।

नोटबंदी

2.10 केंद्र सरकार ने 2016 के नवंबर में, 500 तथा 1000 रु0 के नोटों की नोटबंदी

करने का एलान किया था। सरकार ने दावा किया था कि इस कदम से भ्रष्टाचार, काले धन तथा जाली मुद्रा के चलन पर अंकुश लगेगा तथा आतंकवाद की काट होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़े दिखाते हैं कि नोटबंदी की कसरत के चलते अमान्य हुए 500 तथा 1000 रु0 के नोटों में से 98.96 फीसद बैंकिंग व्यवस्था में लौट आए थे। यह सरकार द्वारा किए जा रहे इस आशय के दावों को झुठला देता है कि नोटबंदी से कम से कम 4-5 लाख करोड़ रु0 का काला धन लौटकर चलन में नहीं आएगा। वास्तव में नोटबंदी से, सरकार का कोई भी दावा पूरा नहीं हुआ है।

2.11 जैसाकि खुद सरकार ने ही आगे चलकर उजागर कर दिया, नोटबंदी के पीछे असली मंशा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में तब्दील करने की थी। नोटबंदी इसकी एक सोची-समझी चाल थी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के लिए व्यापार के मुनाफादेह अवसरों के दरवाजे खोले जाएं। वास्तव में यह सरकार के बड़े धमाकेवाले कदमों का ही हिस्सा था कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे धकेला जाए ताकि बड़े कार्पोरेटों तथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड तथा ई-वॉलेटों का संचालन करने वाले बैंकों को फायदा पहुंचाया जा सके। डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में इस बदलाव का मकसद यही है कि हमारे वित्तीय खुदरा क्षेत्रों में विदेशी कार्पोरेटों के प्रवेश में मदद की जाए। यह इसकी भी कोशिश थी कि भारतीय कार्पोरेटों को और ऋण मुहैया करने के लिए संसाधन जुटाने के जरिए, परोक्ष रूप से उनको भी फायदा पहुंचाया जाए। जो धन जमा कराया गया था उसका उपयोग उन बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करने के लिए किया गया, जो इन्हीं कार्पोरेटों द्वारा ऋण न चुकाए जाने के चलते, जिनके ऋण सरकार ने डूबे हुए ऋणों के तौर पर बट्टे-खाते में डाल दिए थे, मार खा बैठे थे।

2.12 नोटबंदी की छोटे खुदरा व्यापारियों पर मार पड़ी है और इसके चलते अनेक छोटे तथा मंझले उद्यम (एसएमई) बंद हो गए हैं, जिसके चलते रोजगारों की बहुत भारी हानि हुई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आजीविका पर गंभीर रूप से असर पड़ा है। किसान न तो अपनी पैदावार बेच पाए हैं और न अगली बोवाई के लिए बीज तथा खाद खरीद पाए हैं। नोट बदलवाने की लाइनों में लगे-लगे सौ से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। सहकारी बैंकों के लेन-देन पर लगायी गयी पाबंदियों ने भी ग्रामीण जनता की कठिनाइयों को बढ़ाया है और खासतौर केरल जैसे राज्यों में बढ़ाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर जनता के भरोसे को गहरा आघात लगा है।

जीएसटी

2.13 जीएसटी का लागू किया जाना जोकि इस सरकार के नवउदारवादी हमले का हिस्सा है, एक कार्पोरेटपरस्त कदम है जिससे जनता पर बोझ बढ़ा है। जीएसटी व्यवस्था ने हमारे संघीय ढांचे को कमजोर किया है, जिसका राज्यों के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इससे अप्रत्यक्ष कराधान बढ़ गया है। जीएसटी ने आम जनता पर, छोटे तथा अति-लघु उद्यमों पर, व्यापारियों पर और असंगठित क्षेत्र के पेशों पर, नये बोझ डाले हैं। उद्योगों तथा सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका बुरा असर पड़ा है, जिससे रोजगार छिने हैं। ऑनलाइन रिटर्न भरने की अनिवार्यता ने छोटे व्यापारियों तथा उद्यमियों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को भी जीएसटी की मार झेलनी पड़ी है। इस तरह के दावों के विपरीत कि जीएसटी से अनेक मालों की कीमतें घटी हैं, सचाई यह है कि इसके असमानतापूर्ण कर ढांचे के चलते, अनेक मालों तथा सेवाओं के दाम बढ़े हैं।

बैंकिंग क्षेत्र और दरबारी पूंजीवाद

2.14 बैंकिंग व्यवस्था पर बड़ी मात्रा में खराब ऋणों का बोझ लदा हुआ है। यह दरबारी पूंजीवाद का ही लक्षण है, जिसे पिछली यूपीए सरकार द्वारा और वर्तमान मोदी सरकार द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा है। 85 फीसद डुबाऊ ऋण कार्पोरेटों तथा बड़े कारोबारियों के ही हैं। मोदी सरकार के पिछले साढ़े तीन साल में, राष्ट्रीयकृत बैंकों के 2,29,082 करोड़ रु0 के ऋण बट्टे-खाते में डाले गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के साथ नीरव मोदी तथा मेहुल चोकसी द्वारा किए गए 11,500 करोड़ रु0 के घोटाले और उनके सीबीआइ की जांच से पहले देश छोड़कर भाग जाने ने, आंखें खोलने वाले तरीके से यह दिखा दिया है कि मोदी निजाम में दरबारी पूंजीपतियों द्वारा कैसी लूट की जा रही है।

2.15 इसके ऊपर से सरकार फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल (एफआरडीआइ) लायी है, जो फाइनेंशियल रिजोल्यूशन कार्पोरेशन को इसके लिए अधिकृत करेगा कि वह किसी बैंक को बेच दे या उसका विलय कर दे या उसके लिए ''बेल इन'' की प्रक्रिया का सहारा ले। इस नये कानून तथा प्रस्तावित तंत्र का इस्तेमाल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बंद करने या उनका विलय करने के औजार के तौर पर किया जाएगा ताकि निजीकरण को आगे बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, ''बेल इन'' के प्रावधान का इस्तेमाल कर जमाकर्ताओं के पैसे को हड़प कर, ऐसे बैंक को सहारा दिया जाए, जिसने बड़े व्यवसाइयों को उदारता से ऋण

दिए होंगे।

निजीकरण की मुहिम

2.16 नवउदारवादी नीतियों पर आक्रामक तरीके से चले जाने के हिस्से के तौर पर, मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर निजीकरण की एक मुहिम छेड़ी है। इसके तीन पहलू हैं: (अ) राजकीय स्वामित्व वाले क्षेत्रों जैसे रक्षा उत्पादन, रेलवे, बैंकिंग आदि का निजीकरण; (ब) राजकीय क्षेत्र के दरवाजे 100 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के लिए खोलना; और (स) बिजली के वितरण, पानी की आपूर्ति और परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं का निजीकरण। इस प्रकार मोदी सरकार, भारतीय तथा विदेशी, दोनों तरह की बड़ी पूंजी को फालतू लाभ दे रही है।

2.17 योजना आयोग को खत्म कर स्थापित किया गया नीति आयोग, निजीकरण की मुहिम का मुख्य चालक बन गया है। उसने सिफारिश की है कि कुल 235 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में से 74 को बंद कर दिया जाए या फिर रणनीतिक बिक्री के रास्ते से बेच दिया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के 20 उद्योगों में रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दे दी है। नीति आयोग ने कहा है कि रेलवे, बैंक तथा बिजली आपूर्ति कंपनियों जैसी राज्य इजारेदारियों के दरवाजे निजी हिस्सेदारी के लिए खोले जाने चाहिए।

2.18 निजीकरण की मुहिम ने सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सभी क्षेत्रों को अपने दायरे में समेट लिया है। प्रतिरक्षा उत्पादन क्षेत्र उसका खास निशाना है। भारत अर्थ मूवर्स लि0 की रणनीतिक बिक्री की जानी है। रणनीतिक साझेदार कार्यक्रम के तहत प्रमुख भारतीय निजी कंपनियों को पनडुब्बियां, हैलीकोप्टर, लड़ाकू विमान आदि बनाने के लिए, विदेशी शस्त्र निर्माताओं के साथ गठजोड़ करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

2.19 इस्पात के क्षेत्र में दुर्गापुर एलॉय इस्पात संयंत्र और सलेम तथा भद्रावती स्पेशल स्टील संयंत्रों को बेच दिया जाएगा। रेलवे में नियमनकारी प्राधिकार का गठन कर दिया गया है, जिसके तहत रेल लाइनों व अन्य सेवाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। पहले ही 400 रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल के तहत पुनर्विकास के लिए पेश किया जा रहा है। कोयला ब्लाकों की निजी खिलाड़ियों के हाथों नीलामी की जा रही है और मौजूदा कोयला खदानों का निजीकरण किया जा रहा है।

2.20 बुनियादी सेवाओं के निजीकरण के जरिए नवउदारवाद पानी, बिजली, परिवहन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सभी बुनियादी सेवाएं को, बाजार में उपलब्ध मालों का रूप दिलाना चाहता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को खासतौर पर निजीकरण का निशाना बनाया जा रहा है। अपने त्रिवार्षिक कार्रवाई एजेंडा के अनुसार नीति आयोग, सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण कराना चाहता है। उसने जिला तथा तालुका स्तर के अस्पतालों में निजी हिस्सेदारी का प्रस्ताव किया है। उसने इसका भी प्रस्ताव किया है कि 50 से कम छात्रों वाले सरकारी स्कूल, पीपीपी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र को सौंप दिए जाएं।

कृषि संकट

2.21 ग्रामीण भारत में मेहनतकश जनता के जीवन तथा आर्थिक गतिविधि के हरेक क्षेत्र में, मिसाल के तौर पर भूमि अधिग्रहण व भूमि सुधार नीति के मामले में, खेती की लागतों तथा उत्पाद के दाम के मामले में, गरीबों को उपलब्ध ऋण तथा बीमा कवरेज के मामले में, खाद्य सुरक्षा के मामले में, मवेशी संसाधनों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में, मोदी सरकार की नीतियों के चलते गंभीर धक्के लगे हैं। नोटबंदी का रोजमर्रा के ग्रामीण आर्थिक जीवन पर तथा तमाम लेन-देनों पर, गहरा नुकसान पहुंचाने वाला तथा संकुचनकारी असर हुआ है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकद लेन-देन का बोलबाला रहता है। कुछ भाजपा-शासित राज्यों में हर प्रकार के मवेशियों की कटाई पर पाबंदी और मवेशियों के व्यापार पर रोकों का किसानों पर बुरा असर पड़ा है।

2.22 आमतौर पर किसान जनता बढ़ते लागत मूल्यों और उत्पाद के अपर्याप्त मूल्यों की दोहरी कैंची में फंसी हुई है। बढ़ते लागत मूल्यों और उत्पाद के अपर्याप्त मूल्यों का, देहात में सभी वर्गों पर एक समान असर नहीं पड़ता है। यह असर बहुत ही विभेदीकृत होता है और बढ़ते लागत मूल्यों का सबसे ज्यादा बोझ गरीब तथा मंझले किसानों पर पड़ता है।

2.23 दो परिघटनाएं हैं जो पिछले तीन वर्षों में रही मूल्य नीति की पहचान कराती हैं। पहली है, अपर्याप्तता। उत्पाद की कीमतें अक्सर किसानों की लागतों की भी भरपाई नहीं कर पाती हैं। दूसरी यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो भले ही अपर्याप्त रूप से ही सही, ऐतिहासिक रूप से साल-दर-साल बढ़ते आये हैं, अब जहां के तहां बने हुए हैं। 2014 के चुनाव अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी ने यह एलान किया था कि वह राष्ट्रीय कृषक आयोग की इसकी सिफारिशों को लागू

करेंगे कि विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), उत्पादन लागत से 50 फीसद ऊपर हो। बहरहाल, सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद, 2015 की फरवरी में भाजपा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफीडेविट दायर किया था, जिसमें उसने कहा था कि इस वादे को पूरा करना असंभव है। पिछले तीन वर्षों में चावल तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी की गयी है, पिछले पांच साल में सबसे कम है।

2.24 नवउदारवाद के तहत घरेलू तथा विश्व बाजार की कीमतों के बढ़ते पैमाने पर जोड़े जाने ने, बहुत ही इजारेदाराना बाजार वातावरणों में तय होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की अति-अस्थिरता का, भारतीय खेती में सक्रिय रूप से आयात किया है। भारत सरकार पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) व्यवस्था की ओर से इसका दबाव डाला जा रहा है कि वह मौजूदा एमएसपी तथा खरीदी की नीति को समेटे क्योंकि उनसे डब्ल्यूटीओ के नियमनों का या उत्पाद विशेष के लिए सहायता की अधिकतम सीमाओं का उल्लंघन होता है। वर्तमान सरकार के इरादे शांताकुमार कमेटी द्वारा 2015 की जनवरी में दी गयी रिपोर्ट से साफ हो जाते हैं, जिसमें भारतीय खाद्य निगम का निजीकरण करने तथा सरकारी खरीद बंद करने की सिफारिश की गयी थी। इन इरादों का पता राज्य सरकारों को दिए गए उस आदेश से भी चलता है, जिसके जरिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर बोनस या उससे ज्यादा एमएसपी देने से रोका गया था। इस आदेश के साथ यह धमकी जुड़ी हुई थी कि केंद्रीय एमएसपी से ज्यादा एमएसपी की घोषणा करने वाले राज्यों में भारतीय खाद्य निगम खरीदी बंद कर देगा। ये इसकी स्पष्ट चेतावनियां हैं कि विश्व व्यापार संगठन तथा अमरीका के दबाव में, भारत सरकार करोड़ों किसानों से किए मूल्य समर्थन तथा खरीदी के अपने वादे से मुकर रही है।

2.25 एनडीए की सरकार ने ग्रामीण व कृषि ऋणों के सिलसिले में यूपीए सरकार की नीतियों के अमल को और तीखा कर दिया है। 2000 के बाद से कृषि ऋणों में नयी जान पड़ने के सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी कार्पोरेट ग्रुप,ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां तथा अन्य संगठन रहे हैं। कृषि आम तौर पर बैंकिंग क्षेत्र के लिए व्यावसायिक महत्व की गतिविधि नहीं रह गयी है, जोकि बहुत ही चिंता की बात है। गरीब और मंझले किसानों के बीच ऋणग्रस्तता तेजी से बढ़ रही है।

2.26 केंद्र तथा राज्यों की भाजपायी सरकारें कार्पोरेट तथा कृषि-व्यावसायिक घरानों के हम में जाने वाली और आम तौर पर किसानों के हितों के खिलाफ जाने वाली नीतियां लागू कर रही हैं। उदारीकरण के बाद के दौर में मूल्य अति-अस्थिरता

और इसके चलते आय की परिवर्तनीयता, किसानों की आत्महत्याओं तथा कृषि की दुर्गति का मुख्य कारण रही है। बहरहाल, किसान संगठनों द्वारा बार-बार इसकी मांग किए जाने के बावजूद, सरकार एक चौतरफा फसल तथा आय बीमा योजना के मुद्दे को अनदेखा करती आयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाइ) सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही गैर-ऋणग्राहक किसानों को कवर करती है। इस तरह छोटे तथा सीमांत किसान और खासतौर पर दलित व आदिवासी समुदाय के ऐसे किसान, बाहर ही छूट जाते हैं क्योंकि वे प्रीमियम नहीं भर सकते हैं।

प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण की लूट

2.27 मोदी राज के आने के बाद से, पहले ही कमजोर पर्यावरणीय नियमनकारी ढांचे तथा प्रशासन तंत्रों पर गंभीर हमला बोल दिया गया है, ताकि उन्हें कमजोर किया जाए और इस तरह कार्पोरेट स्वार्थों तथा अमीरपरस्त विकास एजेंडा का रास्ता आसान किया जाए। मौजूदा राज के तहत विभिन्न पर्यावरणगत नियमनों को गंभीर रूप से कमजोर किया गया है। औद्योगिक या ढांचागत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरियां और यहां तक कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वन्य तथा तटीय क्षेत्रों तक में ऐसी मंजूरियां आम बात हो गयी हैं, जबकि पर्यावरणीय आकलन में समुचित परिश्रमशीलता एक दुर्लभ चीज हो गयी है। निष्कर्षणकारी उद्योगों के लिए, जिसमें वन्य व तटीय क्षेत्रों में कोयले का खनन भी शामिल है, धड़ाधड़ मंजूरियां दी गयी हैं और वह भी ऐसे खनन से जुड़ी सड़कों व अन्य बुनियादी ढांचे के साथ। नाजुक वन्य जीव अभयारण्यों तक में ऐसी इजाजतें दी गयी हैं। इसके लिए वनाधिकार कानून, अनुसूचित जनजाति कानून, वन्य प्राणी कानून, तटीय क्षेत्र नियमनों और अन्य अनेक विधायी प्रावधानों को पांवों तले कुचला गया है या सीधे-सीधे उनका उल्लंघन किया गया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआइए) की संस्थागत व्यवस्थाओं को अब, ईआइए को राज्यों को हस्तांतरित करने के जरिए, ढांचागत रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह प्राकृतिक संसाधनों के लुटेरे शोषण तथा पर्यावरण के घनघोर विनाश के लिए दरवाजे चौपट खोल दिए गए हैं। इसका हाशिए पर पड़े तबकों जैसे वनवासियों, आदिवासियों, मछुआरों आदि की जिंदगियों और आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा।

जनता के हालात

बेरोजगारी

2.28 मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी रोजगार के मामले में है। सेंटर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआइई) के आंकड़ों के अनुसार 2017 में जनवरी-अप्रैल के दौरान, इससे पहले के चार महीने यानी 2016 के सितंबर-दिसंबर की तुलना में करीब 15 लाख रोजगार छिन गए थे। हर महीने करीब 10 लाख लोग श्रम शक्ति में जुड़ते हैं, जिनमें से अधिकांश को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और वे बेरोजगार रह जाते हैं। नोटबंदी के चलते श्रम में हिस्सेदारी की दर 2016 के जनवरी-अक्टूबर के 46.9 फीसद के औसत के मुकाबले घटकर, 2017 के अप्रैल में 43.5 फीसद रह गयी थी। नोटबंदी के धक्के के अलावा नये निवेशों का अभाव तथा आर्थिक मंदी, श्रम भागीदारी की दरों में गिरावट के मुख्य कारण हैं। यह गिरावट बेरोजगारों की बढ़ती संख्या की ओर ले जाती है। ओईसीडी के 2017 के भारत के आर्थिक सर्वे के अनुसार, 15 से 29 वर्ष तक आयु के 30 फीसद से ज्यादा युवा न तो रोजगार में लगे हुए हैं और न शिक्षा या प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं।

असमानताएं

2.29 उदारीकरण के 25 साल बाद भारत, दुनिया के सबसे असमानतापूर्ण समाजों में से एक हो गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित, 2016 के एक अध्ययन ने यह दिखाया था कि भारतीयों में सबसे धनी, 1 फीसद के पास, देश की समूची संपदा का 28 फीसद था। 1991 में यह हिस्सा 11 फीसद था। ग्रामीण इलाकों में शीर्ष 10 फीसद के हाथों में संपत्तियों का औसत, सब से नीचे के 10 फीसद के मुकाबले, लगभग 228 गुना ज्यादा है, जबकि शहरी इलाकों में शीर्ष 10 फीसद औसत परिसंपत्तियां, सबसे नीचे के 10 फीसद के मुकाबले, करीब 50,000 गुना ज्यादा हैं। परिसंपत्तियों के वितरण की असमानता शहरी भारत में ज्यादा नजरों में चढ़ने वाली है, जहां शीर्ष 10 फीसद का कुल परिसंपत्तियों के 63 फीसद पर स्वामित्व है, जबकि ग्रामीण इलाकों में शीर्ष 10 फीसद का स्वामित्व 48 फीसद पर है। ऑक्सफैम की ताजातरीन रिपोर्ट बताती है कि 2017 में देश में पैदा हुई अतिरिक्त संपदा का 73 फीसद, सबसे ऊपर की 1 फीसद आबादी के हिस्से में गया था।

खाद्य सुरक्षा और आधार

2.30 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए मिलने वाले राशन तक पहुंच के लिए आधार की बायोमीट्रिक पहचान का अनिर्वाय बनाया जाना, लाखों परिवारों के बाहर रखे जाने का औजार बन गया है। बायोमीट्रिक प्रमाणन के विफल होने तथा आधार कार्ड की सीडिंग के जरिए, बड़ी संख्या में गरीबों को राशन पाने से वंचित किया जा रहा है। राशन की आपूर्ति से इंकार किए जाने के चलते झारखंड में तथा दूसरी जगहों पर, भूख की वजह से मौतें हुई हैं। खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों को अनेक राज्यों में सही तरह से लागू नहीं किया जा रहा है और केंद्रीय दिशा निर्देश बड़ी संख्या में सुपात्रों को प्राथमिकता का दर्जा हासिल करने से रोक रहे हैं। इसने केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तहस-नहस कर दिया है। इस सबके चलते जनता के लिए खाद्य सुरक्षा पर गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है।

2.31 आधार कुल मिलाकर निगरानी की एक मुकम्मल व्यवस्था बन गया है और नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, यूआइडीएआइ का डॉटा बेस, वाणिज्यिक दोहन करने के लिए निजी स्वार्थों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

पैट्रोल तथा डीजल के दाम में बढ़ोतरी

2.32 मोदी सरकार द्वारा 2014 से जनता को तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों में भारी गिरावट के लाभ से वंचित रखा गया था। पिछले तीन साल में इस सरकार ने पैट्रोल तथा डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में नौ बार बढ़ोतरी की थी। इसके चलते एक लीटर पैट्रोल के दाम में कर का हिस्सा 21.48 रु0 हो गया है और एक लीटर डीजल के दाम में 17.33 रु0। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में बढ़ोतरी का रुझान आने के साथ पैट्रोल तथा डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। सरकार, एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर के जनता को राहत देने से इंकार कर रही है।

मजदूरों पर हमले

2.33 नवउदारवादी नीतियों पर चलते हुए भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार ने मजदूरों के शोषण को तेज करने को सुगम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उसने मालिकान के हित में और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनस' को बढ़ाने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन करने की प्रक्रिया को तेज किया है। एपरेंटिस (संशोधन) कानून और श्रम कानूनों में संशोधन के कानून को पहले ही लाया जा चुका है।

संसद में पेश किया गया मजदूरी कोड विधेयक और औद्योगिक संबंधों व सामाजिक सुरक्षा के प्रस्तावित कोड, मजदूरों को बुनियादी अधिकारों से वंचित करेंगे, जिसमें संगठन बनाने, सामूहिक सौदेबाजी करने तथा सामाजिक सुरक्षा के उनके अधिकार भी शामिल हैं। अनेक भाजपा-शासित राज्यों की सरकारों ने श्रम कानूनों में संशोधन किए हैं। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे भी अनुकरण करें।

2.34 संगठित क्षेत्र में ठेका तथा कैजुअल मजदूरों का हिस्सा बढ़ा है। सरकार ने सभी क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के रोजगार की इजाजत देने का फैसला लिया है, जो मजदूरों को सेवा की निरंतरता आदि से वंचित करेगा। यह श्रम के ठेकाकरण को तेज करेगा। श्रम ब्यूरो की पांचवी सालाना रोजगार-बेरोजगारी सर्वे रिपोर्ट, 2015-16 (यह सर्वे 2015 के अप्रैल से दिसंबर की बीच किया गया) के अनुसार, देश के 77 फीसद परिवारों में कोई भी नहीं था जो नियमित मजदूरी/ वेतन पर लगा हुआ हो। नियमित मजदूरी/ वेतन पर लगे लोगों में से 57.2 फीसद की आय 10,000 रु0 से कम है। ठेका मजदूरों में 38.5 फीसद और कैजुअल वर्करों में 59.3 फीसद की आय 5,000 रु0 से कम है। विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूरों की विशाल संख्या है, जो बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं, सामाजिक सुरक्षा के संरक्षण से महरूम हैं और भेदभाव के शिकार हैं।

2.35 नारी श्रम शक्ति की भागीदारी जो 2013-14 में 25.8 फीसद थी, अब घटकर 23.7 फीसद रह गयी है। सरकार भारतीय श्रम सम्मेलन की इस सिफारिश को लागू करने से इंकार कर रही है कि सरकारी योजनाओं में काम कर रहे हजारों मजदूरों को, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, मजदूरों के रूप में मान्यता दी जाए, उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाए तथा उनके लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का प्रावधान किया जाए। सरकार इन योजनाओं का निजीकरण करने तथा उन्हें खत्म ही करने के लिए कदम उठा रही है।

2.36 नोटबंदी के चलते लाखों मजदूर अपना रोजगार तथा आय गंवा बैठे। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआइई) के आंकड़ों के अनुसार, 2016 के अक्टूबर और 2017 के अक्टूबर के बीच, 90 लाख रोजगार छिने थे। अधिकांश सूचीबद्ध कंपनियों ने 2016-17 में अपने यहां रोजगार में गिरावट दर्शायी है।

महिलाओं का दर्जा: अधोगति

2.37 पिछले चार साल में आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा स्वायत्तता के महिलाओं के

अधिकारों के मामले में अधोगति हुई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा—यौन हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा व घरेलू हिंसा—हत्याओं, साइबर अपराध तथा दलित महिलाओं के खिलाफ जाति आधारित हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। 2016 में बलात्कार के हर रोज औसतन 106 मामले दर्ज कराए जा रहे थे और महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों में पिछले वर्ष यानी 2015 के मुकाबले 2.9 फीसद की बढ़ोतरी हुई थी। सबसे विचलित करने वाली बात है, बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों में 82 फीसद बढ़ोतरी। कार्यस्थलों पर महिलाओं को तंग किए जाने में भारी बढ़ोतरी हुई है। विकलांग बच्चों तथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी बढ़ी है। फिर भी, आरोपियों को सजा दिए जाने की दर कम बनी हुई है। दूसरी ओर, महिलाओं को सुरक्षा देने वाले कानूनों, जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा, 498ए को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। इसके अलावा निर्भया कोष का बहुत कम उपयोग हो रहा है। यह महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और वर्मा की सिफारिशों को लागू करने में मोदी सरकार की पूर्ण विफलता को दिखाता है।

2.38 अपने आर्थिक व सामाजिक अधिकारों पर दुहरे हमलों के सामने, गरीब महिलाओं, अनुसूचित जाति की तथा आदिवासी महिलाओं की स्थिति सबसे कमजोर रही है। आधार संबंधी समस्याओं के चलते महिलाओं को विधवा या वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। महंगाई, खाद्य सुरक्षा का कमजोर किया जाना, महिला स्वयं सहायता ग्रुपों की जरूरतों की आपराधिक उपेक्षा, इस सब की महिलाओं पर भारी मार पड़ी है। संस्थागत ऋण की अनुपलब्धता उन्हें लुटेरे महाजनों और माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन्स के शिकंजे में धकेल देती है। इस दौर में हालांकि पहले से ज्यादा महिलाएं काम खोज रही थीं, रोजगार के अभाव के चलते महिलाओं की काम में हिस्सेदारी की दर घट गयी है। नोटबंदी के चलते असंगठित क्षेत्र में महिलाओं पर बहुत बुरी मार पड़ी है। इसके साथ ही साथ मनरेगा के अंतर्गत काम के मौकों में भी भारी कटौती हो रही है।

2.39 आम महिलाओं के बीच, धार्मिक विश्वासों तथा परंपराओं के नाम पर, हिंदुत्ववादी विचारधाराओं का सबसे आक्रामक तरीके से प्रचार किया जा रहा है। इसकी अभिव्यक्ति लड़कियों की नैतिक चौकीदारी, स्वयंभू गुंडा गिरोहों और यहां तक कि एंटी-रोमियो दस्तों जैसी शासन द्वारा अनुमोदित संरचनाओं में भी होती है। इसकी अभिव्यक्ति घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून तथा प्री-कसैप्शन एंड प्री-नेटल डाइग्नोस्टिक टैक्नीक्स एक्ट, 1994 (पीएनडीटी कानून) को कमजोर करने की कोशिशों में भी होती है। जनतांत्रिक महिला आंदोलनों द्वारा इन कोशिशों का

मजबूती से प्रतिरोध किया जा रहा है। हालांकि यह सरकार, निजी कानून के दायरे में न्याय के लिए मुस्लिम महिलाओं के संघर्षों का अपहरण करने की कोशिश कर रही है, उसने कथित रूप से इज्जत के नाम पर अपराधों के खिलाफ, जो बढ़ रहे हैं, कोई भी कानून लाने से इंकार कर दिया है। आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठनों के आम सांप्रदायिक हमले के चलते, अल्पसंख्यक तत्ववादी ताकतों में भी बढ़ोतरी हुई है। दोनों तरफ से महिलाओं के बराबर का नागरिक होने के अधिकारों को निशाना बनाया जा रहा है।

2.40 मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को करीब-करीब ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। इन सभी मुद्दों पर, महिलाओं के अधिकारों तथा हैसियत की हिफाजत करने के लिए, महिलाओं के वामपंथी तथा जनतांत्रिक संगठन अगली कतार में रहे हैं। आरएसएस लंबे अर्से से आरक्षण का इस आधार पर विरोध करता आया है कि इससे पारिवारिक जीवन में खलल पड़ेगा।

दलित: बदतर होते हालात

2.41 केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा नवउदारवादी सुधारों पर आक्रामक तरीके से चले जाने की सबसे बुरी मार दलितों पर पड़ी है। सामाजिक कल्याण व गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटनों में भारी कटौतियां, गरीबों तथा खासतौर पर दलितों की जिंदगियों पर तबाही बरपा कर रही हैं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अनेक छात्रों को आधार की समस्याओं के चलते अपनी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। एनडीए सरकार ने केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति घटक योजना के प्रावधान को त्याग दिया है और इन तबकों के विकास पर भारी प्रहार किया है। रोजगारहंता विकास, राज्य व केंद्र दोनों के स्तर पर सरकारी सेवाओं तक में नियमित रोजगार पर प्रतिबंध, काम का ठेकाकरण, चौतरफा निजीकरण, निजी क्षेत्र में आरक्षणों का अभाव, कमजोर तबकों के लिए आरक्षण को ही खत्म कर रहे हैं और इस तरह शिक्षित दलित युवाओं के बीच बेरोजगारी को खासतौर पर चिंताजनक बना रहे हैं।

2.42 दलितों के खिलाफ अपराध लगातार जारी हैं। दलितों पर अत्याचारों के आंकड़े 2015 से 2017 के दौरान निरंतर बढ़ोतरी दिखाते हैं। वास्तव में ये अपराध और ज्यादा होंगे क्योंकि दलितों को अक्सर एफआइआर ही दर्ज नहीं कराने दिया जाता है। हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के नाम पर जातिवादी पूर्वाग्रहों को नंगई से जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसने प्रभुत्वशाली जातियों के

कुछ हलकों के इसके हौसले और बढ़ाए हैं कि वे बिना किसी डर के दलितों के साथ भेदभाव करें तथा उनके खिलाफ अत्याचार करें। अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण कानून के प्रावधानों को कमजोर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हालात और बिगड़े हैं। दलित गऊ -गुंडों के हमलों का निशाना बन गए हैं। सभी मवेशियों के कटने पर पाबंदी और पशु व्यापार पर रोक की मार चमड़े के व्यापार तथा चमड़े के सामान के निर्माण के काम में लगे अनेक दलितों की आजीविका पर पड़ी है। हालांकि, दलितों के मैला ढोने पर कानूनन रोक लगी हुई है, यह अपमानजनक चलन अब भी जारी है और उसे खत्म करने में सरकार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है।

2.43 जातिवादी भेदभाव, अपने साथ रोज-रोज होने वाले उत्पीड़न और सरकार की नीतियों के चलते अपने बढ़ते हाशियाकरण के चलते, दलितों के बीच असंतोष तथा गुस्सा बढ़ रहा है। उनका गुस्सा, अत्याचारों व अपमानों के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध में अभिव्यक्त हो रहा है। आंबेडकर भवन के ध्वस्त किए जाने के खिलाफ मुंबई में गोलबंदी, उना में दलितों पर कोड़े लगाए जाने की घटना के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के खिलाफ देशव्यापी विरोध आंदोलन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों पर हमलों के खिलाफ भीम आर्मी द्वारा की गयी गोलबंदी और भीमा-कोरेगांव की सालगिरह के आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचे दलितों पर हमलों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महाराष्ट्र में बंद, अजा/अजजा अत्याचार निवारण कानून के कमजोर किए जाने के खिलाफ अखिल भारतीय बंद, इस बढ़ते प्रतिरोध के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।

2.44 जनता का सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की अपनी परियोजना के हिस्से के तौर पर, भाजपा तथा आरएसएस सांप्रदायिक आधार पर दलितों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे आंबेडकर की विरासत को हड़पने की और उन्हें हिंदुत्व का पैरोकार तथा इस्लाम का विरोधी बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जनतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इन तिकड़मों को पहचानना चाहिए और इन ताकतों के शरारतपूर्ण मंसूबों को विफल करना चाहिए। सामाजिक न्याय के लक्ष्य के लिए दलितों तथा अन्य कमजोर तबकों की गोलबंदी को, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण आधार बनना चाहिए।

आदिवासियों के अधिकारों पर हमले

2.45 हिंदुत्ववादी विचारधाराओं के प्रचारकों तथा आरएसएस के आदिवासी संगठनों के हमले के जरिए, जो इतिहास के ब्राह्मणवादी पाठ के अनुरूप आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, आदिवासी पहचान तथा आदिवासियों की जीवन पद्धति को एकसार बनाने तथा उसका हिंदूकरण करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ, कारोबार की सुगमता के नाम पर, आदिवासियों की बसाहट के इलाकों में, आक्रामक पूंजीवादी नीतियों के जरिए, उनकी परंपरागत आजीविकाओं को तहस-नहस किया जा रहा है, जिसमें गौण वन उत्पादों तक उनकी पहुंच भी शामिल है। यह भाजपा के राज में आने वाले भारत के अधिकांश हिस्से में बड़े पैमाने पर विस्थापन, पलायन तथा आदिवासी समुदायों के सर्वहाराकरण की निर्मम प्रक्रिया की ओर ले जा रहा है। इसका आदिवासी समुदायों पर दूरगामी तबाही करने वाला असर हो रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में उनकी आर्थिक वेध्यता बढ़ रही है, खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है, स्वास्थ्य की स्थिति गिर रही है और कुपोषण बढ़ रहा है। लड़कियों तथा लड़कों के आदिवासी छात्र होस्टलों की स्थिति दयनीय है और छात्रवृत्तियां देने में आपराधिक देरियां तथा छात्रवृत्तियों के फंड बढ़ाने से इंकार, आदिवासी छात्रों के साथ प्रत्यक्ष भेदभाव के ही रूप हैं, जिनमें से अनेक को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र हासिल करने में देरी की चलते भी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर संघर्ष खड़े करने होंगे।

2.46 कंपन्सेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एक्ट (सीएएमपीए) जैसे कानूनों का पेश किया जाना, खनिज तथा खदान (नियमन तथा विकास) कानून में आदिवासीविरोधी संशोधन किया जाना, आदिवासियों की जमीनों के हड़पे जाने को मंजूरी देता है, जो बड़े पैमाने पर विस्थापन पैदा करता है। झारखंड में भाजपा की सरकार ने, छोटा नागपुर तथा संथाल परगना टेनेंसी कानूनों में संशोधन करने की कोशिश की थी, ताकि आदिवासियों की जमीनों के अधिग्रहण का रास्ता बनाया जा सके। लेकिन, आदिवासियों के संयुक्त संघर्ष ने उन्हें ये संशोधन वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया हालांकि अब नये रूप में ये संशोधन लाने की दोबारा कोशिश की जा रही है। वनाधिकार कानून को, जो कि एक युगांतरकारी कानून है, उसके नियमों में उत्तरोत्तर ऐसे बदलाव करने के जरिए जो ग्राम सभाओं की भूमिका को खत्म करते हैं, कमजोर किया जा रहा है। पंचायत (एक्सटेंशन टु शिड्यूल्ड एरियाज) एक्ट (पीईएसए) का तथा पांचवीं अनुसूची

के प्रावधानों का कमजोर किया जाना, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति मोदी सरकार की हिकारत को दिखाता है।

2.47 आदिवासी अधिकारों के खिलाफ आर्थिक, कानूनी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में, मोदी सरकार तथा भाजपा के नेतृत्ववाली राज्य सरकारों द्वारा छेड़े गए चौतरफा हमले के खिलाफ, इस दौर में आदिवासियों के जुझारू संघर्ष सामने आए हैं। इनमें से अनेक आंदोलनों को पुलिस दमन तथा गोलीबारी का सामना करना पड़ा है। माओवादियों से लड़ने के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को झूठे ही गिरफ्तार किया जा रहा है या राज्य के बलों के हाथों दमन का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आदिवासी महिलाओं पर यौन हमले भी शामिल हैं। माओवादी राजनीति का विरोध करते हुए भी, शासन के दमन के खिलाफ जनतांत्रिक गोलबंदी जरूरी है।

अल्पसंख्यक घेराव में

2.48 दक्षिणपंथी हमले ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच डर तथा असुरक्षा का वातावरण बना दिया है। तथाकथित गोरक्षकों द्वारा निर्दोष मुस्लिम पुरुषों व लड़कों की हत्याओं और ऐसी घटनाओं से निपटने में भाजपा-शासित राज्यों में प्रशासन के खुले पूर्वाग्रह ने, इस असुरक्षा को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपायी राज्य सरकारों ने कट्टीखाने तथा मांस की खुदरा दूकानें बंद कर, लाखों मुसलमानों की आजीविका को निशाना बनाया है। हर प्रकार के मवेशियों को काटने पर रोक के चलते, मवेशियों तथा मांस के व्यापार में लगे मुसलमानों की आजीविका छिनी है। खासतौर पर मध्य प्रदेश तथा झारखंड जैसे भाजपा शासित राज्यों में विभिन्न स्थानों पर ईसाइयों के गिरजों तथा समागमों पर हमले हुए हैं।

2.49 लोगों को 'आतंकवादी' तथा 'राष्ट्रीविरोधी' करार देने की सरकारी लफ्फाजी के चलते, निर्दोष मुस्लिम युवाओं के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट तथा राजद्रोह के कानूनों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। दमन का इस तरह का वातावरण ही मुस्लिम तत्ववाद तथा अतिवाद की बढ़ने में मदद करता है। पार्टी तथा जनसंगठनों को मुसलमानों के परेशान किए जाने तथा निशाना बनाए जाने के सभी मुद्दों को उठाना चाहिए। इन मुद्दों को जनतांत्रिक अधिकारों पर हमलों के वृहत्तर मंच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का हमला अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता तथा अतिवाद की गतिविधियों के लिए जमीन तैयार कर रहा है। इस तरह के रुझान अल्पसंख्यकों के हितों के लिए नुकसानदेह हैं और

उनकी काट की जानी चाहिए ताकि हिंदुत्ववादी ताकतों के खतरे का मुकाबला करने के लिए, जनता की एकता कायम की जा सके।

सामाजिक मुद्दों को आगे ले जाना

2.50 एक के बाद एक पार्टी कांग्रेसें इसके महत्व पर जोर देती आयी हैं कि सामाजिक मुद्दों को उठाया जाए और उन्हें पार्टी के आम राजनीतिक मंच के साथ जोड़ा जाए। यह इसलिए और भी महत्वूर्ण हो गया है कि हिंदुत्ववादी हमला महिलाओं, बच्चों, दलितों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को निशाना बना रहा है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के अभियान में पार्टी को सक्रिय रहना चाहिए। पार्टी को जातिवादी उत्पीड़न व भेदभाव के खिलाफ मुद्दों का और खासतौर पर दलितों तथा सबसे पिछड़े वर्गों के मामले में ऐसे मुद्दों का झंडाबरदार बनना चाहिए। पार्टी को दलित तथा आदिवासी मंचों की गतिविधियों का अपना पूर्ण समर्थन देना चाहिए।

हिंदुत्व का हमला

2.51 पिछले करीब चार साल में इसका नक्शा सामने आया है कि किस तरह आरएसएस, राजसत्ता का इस्तेमाल कर अपने लोगों को, शासन की विभिन्न संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर घुसा रहा है। नियुक्त किए गए राज्यपालों में से ज्यादातर भाजपा-आरएसएस के लोग हैं, जिनमें से कुछ अपने पद का इस्तेमाल कर सांप्रदायिक एजेंडा की वकालत करते हैं। संवैधानिक निकायों को भीतर से खोखला किया जा रहा है। भाजपा और आरएसएस के नेता खुलेआम संविधान को बदलने की अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं।

2.52 शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं का संप्रदायीकरण हो रहा है। यूजीसी, एनसीईआरटी, आइसीएचआर तथा आइसीएसएसआर जैसी संस्थाओं में प्रमुख के पद पर ऐसे लोगों को बैठाया गया है जो या तो आरएसएस के हैं या हिंदुत्व की ओर झुकाव रखते हैं। जेएनयू, एचसीयू तथा पोंडिचेरी विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर हमला किया गया है। वहां पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु बदलने, शिक्षकों को अनुशासित करने की कोशिशें की गयी हैं और छात्र संघों तथा संगठनों पर हमले किए गए हैं। इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है और धर्मनिरपेक्ष व वैज्ञानिक ऐतिहासिक काम को खारिज किया जा रहा है। वैज्ञानिक संस्थाओं तथा विज्ञान पर हमला हो रहा है, जिसकी जड़ें प्रतिगामी हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण में हैं। वैज्ञानिक संस्थाओं तथा शोध के लिए आवंटनों में कटौती की गयी है। पोंगापंथी

विचारों तथा धार्मिक अंधविश्वासों पर आधारित विज्ञानविरोधी विचारों को, सरकारी तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह के विचार महिलाओं पर दोहरी मार करते हैं और इस हिंदुत्ववादी नजरिए के साथ फिट बैठते हैं कि महिला को पुरुष के आधीन होना चाहिए।

2.53 जहां ऊपर से केंद्र सरकार द्वारा हिंदुत्व के एजेंडा को थोपा जा रहा है, जमीनी स्तर पर आरएसएस के नेतृत्ववाले हिंदुत्ववादी संगठनों को खुली छूट मिली हुई है। मुसलमानों को निशाना बनाने की नीयत से, कथित गोरक्षक गिरोह पशु व्यापारियों या किसानों को निशाना बना रहे हैं और हत्यारी भीड़ के हमले करा रहे हैं। गोहत्या या गोमांस के नाम पर इस तरह के फासिस्टी किस्म के इन हमलों में पिछले तीन साल में तीस से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। भाजपा-आरएसएस की राज्य सरकारें खुले आम इन गो-गुंडों को संरक्षण तथा समर्थन दे रही हैं। ''लव जेहाद'' के लिए मुसलमानों का निशाना बनाया जाना तथा उन्हें राष्ट्रविरोधी करार दिया जाना, ऐसे अन्य हथियार हैं जिनका इस्तेमाल हिंदुत्व की पलटन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए करती है। रामनवमी जैसे धार्मिक त्यौहारों के दौरान व्यवस्थित तरीके से सांप्रदायिक दंगे कराए जा रहे हैं।

2.54 इन गिरोहों का एक और निशाना पशु व्यापार तथा मरे पशुओं की खाल उतारने के काम से जुड़े दलित हैं। गुजरात में उना में चार दलित नौजवानों की नृशंसता से पिटाई, इसी दलितविरोधी मुहिम का हिस्सा थी।

2.55 हिंदुत्ववादी अतिवादी गिरोहों ने ऐसे बुद्धिजीवियों तथा लेखकों को खासतौर पर निशाना बनाया है जो तर्कवादी तथा धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रचार करते हैं। दाभोलकर की हत्या के बाद महाराष्ट्र में पानसरे की हत्या की गयी थी। कर्नाटक में प्रोफेसर कलबुर्गी इन ताकतों का निशाना बन गए। इन ताकतों ने फिर प्रहार किया और गौरी लंकेश की हत्या कर दी। इस तरह के फासिस्टी हमलों का मकसद, हिंदुत्व के विरोधियों को धमकाना और चुप कराना है।

जम्मू-कश्मीर

2.56 पिछली पार्टी कांग्रेस के बाद से कश्मीर घाटी में हालात में भारी गिरावट आयी है। जैसीकि तब आशंका थी, इस राज्य में पीडीपी-भाजपा गठजोड़ सरकार के बनने से, जम्मू और घाटी के बीच सांप्रदायिक विभाजन तीखा ही हुआ है। व्यवहार में

मोदी सरकार का रवैया यही रही है कि जम्मू-कश्मीर को किसी भी प्रकार के विशेष दर्जे से वंचित रखा जाए। इसका नतीजा यह हुआ है कि भारतीय शासन से घाटी की जनता का अलगाव उस हद तक बढ़ गया है, जिस हद तक इससे पहले कभी नहीं पहुंचा था।

2.57 सुरक्षा बलों द्वारा 2016 की जुलाई में हिज्बुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट बुरहान वानी के मारे जाने से एक जबर्दस्त जन उभार आया था। इसे सुरक्षा बलों ने नृशंसता से दबाया। 6000 से ज्यादा नौजवान घायल हुए और छर्रेवाली बंदूकों के इस्तेमाल के चलते 500 से ज्यादा की आंखों में घाव आए, जिनमें से अनेक की एक आंख की या दोनों आंखों की रौशनी ही चली गयी। इस तरह के दमन से मिलिटेंसी को बढ़ावा मिला और यह सुरक्षा बलों के दमनचक्र की ओर ले गया। जहां मिलिटेंट गतिविधियों पर किसी हद तक अंकुश लग गया है, जनता का अलगाव गहरा बना हुआ है।

2.58 मोदी सरकार ने असंतोष तथा अलगाव से बल प्रयोग के जरिए निपटने की कोशिश की है। उसने न तो राजनीतिक संवाद शुरू करने की पुकारों को सुना है और न उस संसदीय प्रतिनिधिमंडल के प्रस्तावों को स्वीकार किया है जिसने 2016 के सितंबर में इस राज्य का दौरा किया था। उल्टे, राज्य के स्थायी निवासियों के अधिकारों की हिफाजत के लिए बनी संविधान की धारा-35 ए को कानूनी चुनौती दिए जाने से हिंदुत्व के एजेंडा के बारे में आशंकाएं और बढ़ गयी हैं। बहुत देर करने के बाद, खुफिया विभाग के एक पूर्व-प्रमुख के वार्ताकार के रूप में नियुक्त किए जाने से केंद्र के इरादों की गंभीरता का कोई भरोसा पैदा नहीं हुआ है।

2.59 सी पी आइ (एम), जम्मू-कश्मीर की समस्या के मामले में मोदी सरकार के राजनीतिक रवैये के पूरी तरह से खिलाफ है। सी पी आइ (एम) अपना यह रुख दोहराती है कि राजनीतिक दायरे के सभी रंगों के साथ राजनीतिक संवाद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ, कश्मीर के मुद्दे के समाधान के लिए पाकिस्तान के साथ रजनीतिक संवाद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, पुलिस दमन का तथा छर्रेवाली बंदूकों के इस्तेमाल का और सशस्त्र बल विशेष शक्तियां कानून (आफस्पा) का अंत होना चाहिए। इसका भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि धारा-370 के मूल रूप में जिन प्रावधानों की कल्पना की गयी थी उन्हें बहाल किया जाए और राज्य के तीनों क्षेत्रों—जम्मू, घाटी तथा लद्दाख—को स्वायत्तता दी जाए।

उत्तर-पूर्व

2.60 नाजुक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मुख्य खतरा यह है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने तथा उसके बाद असम में भाजपा सरकार बनने के बाद से, सांप्रदायिक तनावों तथा इथनिक झगड़ों के लिए इस क्षेत्र में उपजाऊ जमीन तैयार की जा रही है। नागरिकता कानून में संशोधन का विधेयक संसद में पेश किए जाने से, जिसके तहत सीमा पार से आने वाले हिंदुओं को खुद ब खुद नागरिकता दे दी जाएगी, असमिया समुदाय के बीच, अन्य इथनिक समुदायों के बीच और विशेष रूप से पूर्वी-बंगाली मूल के मुसलमानों के बीच, बहिष्करण की आशंकाएं पैदा हुई हैं। नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में, 1971 के मार्च की कट ऑफ तिथि के आधार पर तथा सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में नामों की भर्ती की प्रक्रिया में, छेड़-छाड़ की कोशिशों से भी दुश्चिंताएं पैदा हो रही हैं। ये दुश्चिंताएं खासतौर पर पूर्वी बंगाल से आए उन लोगों के बीच पैदा हो रही हैं, जो आजादी से पहले से असम में बसे हुए हैं। भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार, असम की विनाशकारी बाढ़ की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या मानने से और उसे हल करने के लिए आवश्यक फंड आवंटित करने से इंकार कर रही है।

2.61 नगा फ्रेमवर्क समझौता, जिसकी अंतर्वस्तु को सार्वजनिक नहीं किया गया है, ग्रेटर नगालैंड की स्थिति के संबंध में, मणिपुर, असम तथा अरुणाचल प्रदेश की जनता के बीच चिंता तथा अशंकाएं पैदा कर रहा है। भाजपा और आरएसएस, अपने सांप्रदायिक एजेंडा के आधार पर विभिन्न इथनिक तथा आदिवासी समुदायों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इन कदमों से सांप्रदायिक तथा इथनिक सौहार्द्र के लिए खतरा पैदा हो रहा है। भाजपा की यही कोशिश है कि स्थानीय अभिजन तथा पार्टियों को अपने पाले में ले आया जाए ताकि वह अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा सके।

2.62 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के चौतरफा विकास की जरूरत पर काम करने से इंकार करने के मामले में, केंद्र की भाजपा सरकार का रुख वही है, जो पिछली सरकारों का था। योजना आयोग के खत्म किए जाने के फलस्वरूप, विकास फंडों का 10 फीसद उत्तर-पूर्व के लिए सुरक्षित किए जाने का अंत हो गया है। इसका इस क्षेत्र के समग्र विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

संघीय व्यवस्था पर हमला

2.63 मोदी सरकार शक्तियों का केंद्रीयकरण करती रही है और व्यवस्थित तरीके से

राज्यों के अधिकारों को कमजोर कर रही है। जीएसटी के लागू किए जाने से, राज्यों को कर लगाने का जो थोड़ा-बहुत अधिकार था भी, उसे भी वे गंवा बैठे हैं। केंद्र सरकार, राज्यों को दिए जाने वाले फंडों में मनमानी कटौतियां थोप रही है। राष्ट्रपति शासन थोपने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल, उत्तराखंड तथा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। पांचवे वित्त आयोग के लिए मोदी सरकार द्वारा तय की गयी विचार शर्तें, संघवाद पर तथा राज्यों के अधिकारों पर एक और हमला है। तमिलनाडु के राज्यपाल और दिल्ली तथा पुदुच्चेरी के उप-राज्यपालों का राज्य के मामलों में दखलंदाजी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ कराने के प्रस्ताव को एक ही तरह से लागू किया जा सकता है कि या तो राज्य विधानभाओं के कार्यकाल को कतरा जाए या राज्य सरकारों को वोट से हटाने की शक्ति पर ही अंकुश लगाया जाए। इस तरह का प्रस्ताव संविधान की बुनियादी विशेषताओं के खिलाफ जाता है।

2.64 केंद्र सरकार तथा उसकी संस्थाओं द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर हिंदी के इस्तेमाल के फरमान थोपे जा रहे हैं और शिक्षा व संस्कृति के मामले में दूसरे निर्देश दिए जा रहे हैं, जो राज्यों के अधिकारों पर हमला करते हैं।

तानाशाहीपूर्ण कदम

2.65 हिंदुत्व और कार्पोरेट सत्ता का योग, तानाशाही की ओर बढ़ने की मुहिम को ईंधन मुहैया करा रहा है। इस दौर में तानाशाहीपूर्ण कदमों की पूरी शृंखला सामने आयी है। मोदी सरकार ने विधेयकों को 'मनी बिल' की श्रेणी में डालने की तिकड़म के जरिए राज्यसभा को धता बताकर, संसद का दर्जा गिराया है। उसने लोगों को राष्ट्रविरोधी करार देने के लिए और असहमति की आवाजों को दबाने के लिए, गैर-कानूनी गतिविधियां निवारक कानून (यूएपीए) और राजद्रोह की धाराओं का इस्तेमाल करने का सहारा लिया है।

2.66 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठतम चार न्यायाधीशों द्वारा किए गए रहस्योद्घाटनों से इस संबंध में चिंतित करने वाले सवाल उठे हैं कि किस तरह कार्यपालिका से आने वाले बाहरी दबाव उच्चतर न्यायपालिका पर अपना असर दिखा रहे हैं। यह सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मंजूरी के आधार पर, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर वीटो का अधिकार हासिल करने की कोशिश कर रही है।

2.67 मीडिया के जो हिस्से उसके मनमुताबिक नहीं चल रहे हैं, उन्हें झुकाने के लिए

मोदी सरकार दाब-धौंस के हथकंडों का सहारा ले रही है। पहले ही कार्पोरेट मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जोरों से भाजपा की उन्मत्त-राष्ट्रवादी तथा हिंदुत्वादी लाइन समर्थन कर रहा है। मुकद्दमे दायर करने की धमकियों, संपादकों के हटवाए जाने और अपने पक्ष में जाने वाली खबरों को दबवाने के लिए दबाव डालने का सहारा लिया जा रहा है।

बड़ी दौलत और भ्रष्टाचार

2.68 मोदी सरकार ने कार्पोरेटों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भ्रष्टाचार और काले धन को वैधता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। चुनावी बांडों का लाया जाना, जिनमें चंदादाताओं के नाम छुपे रहेंगे, ऐसी स्थिति की ओर ले जाएगा जहां चुनावी बांडों के माध्यम से सत्ताधारी पार्टी को, ठेकों के लिए दलाली दी जा रही होगी। इसमें चंदादाता का नाम, न तो बांड देने वाली सत्ता को बताना होगा और न बांड से पैसा पाने वाली पार्टी को। पुन: सरकार ने उस कानून में भी संशोधन कर दिया है, जो किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए, संबंधित कंपनी के शुद्ध मुनाफे (तीन साल का औसत) के 7.5 फीसद की अधिकतम सीमा लगाता था। इस अधिकतम सीमा के हटाए जाने के बाद, कानूनी तौर पर बहुत बड़ी राशियां दी जा सकेंगी। यह बड़े पैमाने पर धन शोधन तथा घूसखोरी को बढ़ावा देगा।

2.69 अपने शासन में शून्य भ्रष्टाचार की शेखी मारने वाली भाजपा सरकार को राफाल लड़ाकू विमान सौदे ने बेनकाब कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री ने पहले से मौजूद आर्डर को बदला है और एक नया समझौता किया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएएल की जगह पर, अनिल अंबानी की कंपनी को 21,000 करोड़ रु0 कीमत के ऑफसैट्स यानी सौदे की कीमत के एक हिस्से के बराबर स्थानीय रूप से उत्पादन के लिए साझीदार बनाया गया है। मध्य प्रदेश में व्यापमं से लेकर, महाराष्ट्र में भूमि तथा चिक्की घोटालों, राजस्थान में खनन घोटाले तथा छत्तीसगढ़ में पीडीएस घोटाले तक, भाजपा-शासित राज्यों में भ्रष्टाचार घोटालों की भरमार है। अमित शाह के बेटे की कंपनी का घोटालापूर्ण प्रकरण, इसी की एक और मिसाल है। मोदी सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए कानून को लागू ही नहीं किया है।

चुनाव सुधार

2.70 चुनावी बांड के जरिए चुनाव में बड़े पैसे के दखल को वैध बनाने के मोदी सरकार के कदम, चुनावी सुधारों की अनिवार्यता तथा उनके तत्काल जरूरी होने को

रेखांकित करते हैं। वीवीपैट मशीनों को सभी इलैक्ट्रोनिक मशीनों के साथ जोड़ा जाना चाहिए और मतगणना के दौरान, कम से कम 20 फीसद वीवीपैट मतों का, मतदान मशीनों के नतीजे के साथ मिलान किया जाना चाहिए। धनबल पर अंकुश लगाने के कदमों का तकाजा है कि चुनाव के लिए राजकीय फंडिंग की व्यवस्था हो। इसके बजाए भाजपा की सरकार ने वित्त विधेयक के माध्यम से, विगत प्रभाव से विदेशी चंदा नियमन कानून में संशोधन कर दिया है ताकि राजनीतिक पार्टियों द्वारा विदेशी फंड लिए जाने को वैधता प्रदान की जा सके। यह संशोधन, बहुराष्ट्रीय निगमों की सब्सीडरियों तथा विदेशी पूंजी द्वारा नियंत्रित कंपनियों को, राजनीतिक पार्टियों को पैसा देने का मौका देता है। इस खतरनाक प्रावधान को निरस्त किया जाना चाहिए। चुनाव प्रणाली में, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लाए जाने के जरिए, एक बुनियादी बदलाव करने की जरूरत है। आंशिक सूची प्रणाली के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लागू किए जाने के पक्ष में पार्टी के रुख का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए।

विदेश नीति: अमरीकी शिविर में

2.71 विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता से अमरीकापरस्त दिशा में बदलाव, 1991 में उदारीकरण की नीतियों के अपनाए जाने के साथ आया था। इन ढाई दशकों में एक के बाद एक आयीं कांग्रेस तथा भाजपा की सरकारें, अमरीका के साथ रणनीतिक गठजोड़ की ओर बढ़ी हैं। यूपीए सरकार के दस साल के शासन के बाद, जिसमें अमरीका के साथ रणनीतिक गठजोड़ कायम करने के लिए और कदम उठाए गए थे, मोदी सरकार ने इस अमरीकापरस्त विदेश नीति को और तेज कर दिया है तथा व्यापक बनाया है।

2.72 जनवरी 2015 में, ओबामा की भारत यात्रा के दौरान जो भारत-अमरीका संयुक्त दृष्टि वक्तव्य स्वीकार किया गया था, उसमें भारत को इसके लिए वचनबद्ध किया गया है कि वह एशिया के लिए अमरीका की धुरी के साथ और एशिया-प्रशांत के लिए उसकी भू-राजनीतिक रणनीति के साथ, तालमेल करेगा। नरेंद्र मोदी ने और भी आगे बढ़कर, जापान तथा अमरीका के साथ त्रिपक्षीय सुरक्षा गठजोड़ कर लिया है और उससे भी आगे भारत को, जापान, आस्ट्रेलिया तथा अमरीका के साथ, अमरीका प्रायोजित चौकोने गठजोड़ का हिस्सा बना दिया है।

2.73 भारत को एक 'प्रमुख रक्षा साझीदार' का दर्जा दिए जाने के साथ, अमरीका के साथ सैन्य गठजोड़ को और गहरा कर दिया गया है। भारत-अमरीका रक्षा रूपरेखा

समझौते का और दस साल के लिए और नवीनीकरण कर दिया गया है। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट यानी एलईएमओए पर दस्तखत किए जाना एक बड़ा कदम है। इससे अमरीकी युद्धपोतों तथा वायु सेना के विमानों को ईंधन भरवाने, सर्विसिंग तथा रख-रखाव के लिए, भारतीय सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी। यह भारत की संप्रभुता का अतिक्रमण है। इससे पहले किसी भी सरकार की इसकी इजाजत देने की हिम्मत नहीं हुई थी।

2.74 इस्राइल के साथ रिश्तों को गहरा बनाया गया है। मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं, जिन्होंने इस्राइल का दौरा तो किया, लेकिन ध्यान खींचने वाले तरीके से फिलिस्तीनी प्राधिकार का दौरा करने से दूर रहे। अमरीकी राष्ट्रपति तक यह दौरा किया करते हैं। परंपरा से हटते हुए प्रधानमंत्री ने कराकास में हुए गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया।

2.75 भारत, 2017 के जून में शांघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया। वह ब्रिक्स का भी हिस्सा है। लेकिन, मोदी सरकार को सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे की चिंता है और वह इन मंचों का क्षेत्रीय सहयोग तथा बहुध्रुवीयता को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही है।

2.76 दक्षिण एशियाई पड़ौसियों के प्रति मोदी सरकार की नीति ने, उनके साथ अच्छे तथा घनिष्ठ संबंधों को बाधित किया है। मधेसी आंदोलन द्वारा नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी का समर्थन कर के भारत ने नेपाल की जनता को और तमाम राजनीतिक ताकतों को नाराज कर दिया। रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर भारत का रुख, बांग्लादेश के लिए रत्तीभर मददगार नहीं है। मोदी सरकार, संवाद की सभी संभावनाओं को त्यागकर, पाकिस्तान के प्रति टकरावादी रुख अपनाए हुए है। यह इसके क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित है कि अंध-राष्ट्रवाद को भड़काया जाए और देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तीखा करने में मददगार हो सकता है।

बढ़ता प्रतिरोध और व्यापक होते संघर्ष

2.77 इस दौर की पहचान मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों, सांप्रदायिक एजेंडा और तानाशाहीपूर्ण हमलों के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध से होती है।

(1) किसानों के एकजुट संघर्ष हुए हैं। इनमें मुख्य हैं: महाराष्ट्र में किसानों की ग्यारह दिन की हड़ताल, जो किसानों के नासिक से मुंबई तक के ऐतिहासिक लान्ग मार्च में अपने उत्कर्ष पर पहुंची, जो कि किसान संघर्षों के इतिहास में एक नया मील का पत्थर बन गया है; मध्य प्रदेश में मंदसौर तथा उससे लगते हुए

जिलों में किसानों के स्वत:स्फूर्त संघर्ष; झारखंड में संथाल परगना तथा छोटा नागपुर टेनेंसी कानून में संशोधन के खिलाफ संघर्ष; और सीकर में तथा राजस्थान के पांच अन्य जिलों में किसानों का व्यापक संघर्ष, जिसे ग्रामीण जनता के सभी तबकों का समर्थन हासिल था। ये संघर्ष राज्य सरकारों से कुछ मांगें मनवाने में सफल रहे हैं। किसान संगठनों के एकजुट संघर्ष भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर करने के मोदी सरकार के कदम को रोकने में सफल रहे थे। 20-21 नवंबर 2017 को हुई किसान संसद में, जिसका आयोजन 187 संगठनों के संयुक्त मंच द्वारा किया गया था, देश भर से किसानों की विशाल गोलबंदी हुई थी। यह हाल के दौर की किसानों की सबसे महत्वपूर्ण एकजुट कार्रवाई थी। इन सभी संघर्षों में अखिल भारतीय किसान सभा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

(2) ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने 2 सितंबर 2016 को एक आम हड़ताल की थी, जिसने मजदूरों तथा कर्मचारियों की साझेदारी को और व्यापक बनाया। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों, इस्पात मजदूरों तथा बीएसएनएल कर्मचारियों की महत्वपूर्ण क्षेत्रवार हड़तालें हुई हैं। बंगलूरु में आंगनवाड़ीकर्मियों का सत्याग्रह संघर्ष और महाराष्ट्र में महीना भर की मुकम्मल राज्यव्यापी हड़ताल, उल्लेखनीय रहे। 2015 के अप्रैल में सड़क परिवहन मजदूरों की पहली अखिल भारतीय हड़ताल हुई जिसमें विशाल हिस्सेदारी देखने को मिली। दिल्ली में संसद के बाहर, 9 से 11 नवंबर 2017 तक हुए मजदूरों के तीन दिन के महापड़ाव की अनोखी विरोध कार्रवाई में, एक लाख से ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया था। इन सभी संघर्षों में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

(3) सांप्रदायिक तानाशाहीपूर्ण हमलों के खिलाफ जेएनयू, एचसीयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों, एफटीआइआइ आदि में छात्रों के संघर्ष हुए हैं। गो-गुंडों द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ फासिस्टी किस्म के हमलों के खिलाफ और लेखकों व पत्रकारों की हत्याओं के खिलाफ जन विरोध कार्रवाइयां तथा रैलियां हुई हैं। कलबुर्गी की हत्या के खिलाफ बड़ी संख्या में जाने-माने लेखकों तथा कलाकारों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए थे। गौरी लंकेश की हत्या के बाद देश भर में विरोध कार्रवाइयां हुई हैं।

(4) रोहित वेमुला की मौत पर तथा दलितों के साथ उना अत्याचार पर देश भर में विरोध कार्रवाइयां हुई थीं और वामपंथी व दलित संगठनों द्वारा एकजुट अभियान चलाए गए थे। दलित स्वाभिमान संघर्ष मंच, वामपंथी पार्टियों तथा

दलित संगठनों के मंच के रूप में सामने आया है, जिसने विभिन्न केंद्रों में रैलियां आयोजित की हैं।

(5) जन एकता, जन अधिकार आंदोलन के नाम से, 2017 के सितंबर में जन व वर्गीय संगठनों तथा सामाजिक आंदोलनों का एक मंच गठित किया गया है। इसने एक मांग पत्र तैयार किया है, जिसके गिर्द एकजुट अभियान तथा संघर्ष छेड़े जाएंगे।

हालात का सार-संक्षेप

2.78 भाजपा ने अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ कर ली है। मोदी सरकार के अंतर्गत जनता का नवउदार पूंजीवादी शोषण तेज हुआ है; हिंदुत्ववादी एजेंडा पर चले जाने के जरिए संविधान के धर्मनिरपेक्ष-जनतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है; और भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार ने भारत को अमरीका की साम्राज्यवादी रणनीति के साथ और कसकर बांध दिया है। यह सब एक आक्रामक नवउदारवादी तानाशाहीपूर्ण-सांप्रदायिक निजाम के आने का सूचक है।

2.79 इसके साथ ही साथ, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसकी अभिव्यक्ति जनता के विभिन्न तबकों के बढ़ते प्रतिरोध तथा संघर्षों में भी हो रही है। एक ओर सत्ताधारी वर्ग और दूसरी ओर मजदूर वर्ग तथा किसानों के बीच अंतर्विरोध बढ़ गया है। हमें इन हालात में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि मेहनतकश जनता के विभिन्न संघर्षों को आगे ले जा सकें।

2.80 जब व्यवस्था पर बड़े पूंजीपति-भूस्वामी वर्ग का प्रभुत्व होता है, विभिन्न मुकामों पर, अलग-अलग रूपों में तानाशाही उभरकर सामने आती है। हमारी कार्यनीति का निशाना बड़े पूंजीपति-भूस्वामी प्रभुत्व को कमजोर करने पर रहना चाहिए, तभी हम कारगर तरीके से तानाशाही के राज से लड़ पाएंगे।

2.81 अपने ऊपर थोपे जा रहे आर्थिक बोझों के खिलाफ मेहनतकश जनता के विभिन्न तबकों के संघर्षों को आगे ले जाने के लिए, पार्टी को अपना हस्तक्षेप बढ़ाना चाहिए। नवउदारवादी नीतियों के असर के खिलाफ इन संघर्षों का, सांप्रदायिक एजेंडा के खिलाफ संघर्षों के साथ योग स्थापित करना ही, भाजपा-आरएसएस जोड़ी के खिलाफ संघर्ष को आगे ले जाने का रास्ता है। नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष तथा तानाशाही के खिलाफ संघर्ष, सभी अविभाज्य तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं।

राजनीतिक पार्टियों की स्थिति

भाजपा

2.82 भाजपा, जैसाकि पार्टी कार्यक्रम ध्यान दिलाता है: ''एक प्रतिक्रियावादी पार्टी है, जिसका ऐसा फूटपरस्त तथा सांप्रदायिक मंच है, जिसकी प्रतिक्रियावादी अंतर्वस्तु अन्य धर्मों के प्रति घृणा, असहिष्णुता और अंधराष्ट्रवादी उन्माद पर आधारित है। भाजपा कोई सामान्य पूंजीवादी पार्टी नहीं है क्योंकि फासीवादी सोच वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस पर हावी है और उसका मार्गदर्शन करता है। भाजपा के सत्ता में रहने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहुंच, सरकारी मशीनरी और राज्यतंत्र के विभिन्न अंगों तक हो गयी है।'' भाजपा, फासिस्टी आरएसएस द्वारा संचालित तथा नियंत्रित है।

2.83 नरेंद्र मोदी के राज में आरएसएस और सरकार का तालमेल, इससे पहले वाजपेयी सरकार के राज के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पुन:, नरेंद्र मोदी, भाजपा के लिए बड़े पूंजीपति वर्ग से कहीं व्यापक समर्थन जुटा सके हैं।

2.84 भाजपा बढ़ी है और उसने बड़े पूंजीपति-भूस्वामी वर्ग की प्रभुत्वशाली राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस को प्रतिस्थापित कर दिया है। राजसत्ता का इस्तेमाल कर भाजपा-आरएसएस जोड़ी ने देश भर में अपना संगठन तथा प्रभाव फैला लिया है। अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए भाजपा, कांग्रेस तथा अन्य पूंजीवादी पार्टियों से दलबदलुओं को अपने साथ मिलाती आयी है। वह ऐसा खासतौर पर उन राज्यों में कर रही है जहां वह कमजोर रही है, मिसाल के तौर पर उत्तर-पूर्व के राज्यों में।

2.85 इस समय भाजपा, देश के 29 राज्यों में से 21 में अकेले या गठबंधन के हिस्से के तौर पर सरकार में है। उसे लोकसभा में बहुमत हासिल है और राज्यसभा में अकेले सबसे बड़ी पार्टी बन गयी है। पहली बार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों भाजपा-आरएसएएस की धारा से हैं।

कांग्रेस पार्टी

2.86 कांग्रेस पार्टी का वर्ग चरित्र वही है, जो भाजपा का है। वह बड़े पूंजीपति-भूस्वामी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। उसका राजनीतिक प्रभाव तथा

संगठन गिरावट पर है और उसने प्रधान सत्ताधारी पार्टी का स्थान भाजपा को दे दिया है। कांग्रेस, धर्मनिरपेक्ष होने का दम भरती है, लेकिन वह सांप्रदायिक ताकतों से अविचल रूप से संघर्ष करने में असमर्थ साबित हुई है। कांग्रेस जब सत्ता में थी, उसने नवउदारवादी एजेंडा की शुरूआत की थी और उसने अमरीका के साथ रणनीतिक गठजोड़ कायम किया था। मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में वह इन नीतियों की वकालत करना जारी रखे हुए है। इन नीतियों का विरोध करना जरूरी है।

2.87 जनता की जनवादी क्रांति के तीन बुनियादी काम हैं—इजारेदारविरोधी, भूस्वामीविरोधी और साम्राज्यवादविरोधी। जैसाकि पार्टी कार्यक्रम ध्यान दिलाता है:

''लेकिन, आज के संदर्भ में क्रांति के ये बुनियादी और आधारभूत कार्यभार, बड़े पूंजीपति वर्ग और राजसत्ता के नेतृत्व पर काबिज उसके राजनीतिक प्रतिनिधियों के दृढ़तापूर्ण विरोध और उनके खिलाफ संघर्ष के बिना पूरे नहीं किए जा सकते हैं।''

2.88 इस समय हमारे देश में बड़े पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक प्रतिनिधि हैं—भाजपा और कांग्रेस। हमारी कार्यक्रमगत समझ के हिसाब से कांग्रेस बड़े पूंजीपति वर्ग तथा भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और साम्राज्यवादपरस्त नीतियां अपनाती है। इसलिए, हम ऐसी कार्यनीतिक लाइन नहीं अपना सकते हैं जो उन्हें किसी संयुक्त मोर्चे में सहयोगियों या साझीदारों के रूप में देखती हो।

2.89 लेकिन, भाजपा ही है जो आज सत्ता में है और आरएसएस के साथ अपने बुनियादी रिश्ते के चलते, वही मुख्य खतरा है। इसलिए, भाजपा और कांग्रेस, दोनों को बराबर का खतरा मानने की लाइन नहीं अपनायी जा सकती है।

क्षेत्रीय पार्टियां

2.90 क्षेत्रीय पार्टियों की बदली हुई भूमिका का 21वीं कांग्रेस द्वारा स्वीकृत राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन की समीक्षा में विश्लेषण तथा समाहार किया गया था। क्षेत्रीय पार्टियां अपने-अपने क्षेत्र के पूंजीपति-भूस्वामी वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनके वर्गीय हित नवउदारवादी नीतियों के प्रति क्षेत्रीय पार्टियों के रुख में अभिव्यक्त होते हैं। हमने उनके अवसरवाद को भी दर्ज किया था, जो केंद्र में गठजोड़ सरकार का हिस्सा बनने के लिए, भाजपा या कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने से मिल सकने वाले अवसरों को हासिल करने की आकांक्षा से निकलता है।

2.91 2014 के चुनाव में जो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा के साथ थीं वे हैं—अकाली

दल, तेलुगू देशम् पार्टी तथा असम गण परिषद। उसके बाद से जनता दल (यूनाइटेड) पालाबदल कर और 2015 के विधानसभाई चुनाव के जनादेश के साथ विश्वासघात करते हुए, दोबारा भाजपा के पास चली गयी है। जयललिता की मृत्यु के बाद, एआइएडीएमके में फूट पड़ गयी। दो प्रमुख गुट फिर से जुड़ गए हैं जिनके बीच भाजपा के नजदीक पहुंचने की होड़ लगी रही थी। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने के मुद्दे पर तेलुगू देशम् पार्टी ने हाल ही में एनडीए से नाता तोड़ लिया है। अन्य सत्ताधारी क्षेत्रीय पार्टियों, जैसे ओडिशा में बीजद तथा तेलंगाना में टीआरएस, शुरूआत में मोदी सरकार का विरोध करने से बचती आयी थीं और भाजपा के साथ समझौता करना चाहती थीं। आंध्र प्रदेश में वाइएसआरसीपी ने भी ऐसी ही मुद्रा अपनायी थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक निरंकुश तथा अलोकतांत्रिक पार्टी है, जो अपनी राजनतिक सत्ता को पुख्ता करने के लिए, भाजपा के साथ प्रतिस्पर्द्धी सांप्रदायिकता का खेल खेलती है।

2.92 दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जिन्होंने भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाए हैं। हमें जहां कहीं भी संभव हो इन पार्टियों के साथ जनता के मुद्दों पर और सांप्रदायिकता तथा तानाशाहीपूर्ण हमलों के खिलाफ, एकजुट कार्रवाइयां विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

2.93 क्षेत्रीय पार्टी विशेष के प्रति अपना कार्यनीतिक रुख तय करते हुए हमें, संबंधित राज्य में पार्टी विशेष की भूमिका तथा राजनीति को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह के नजरिए में पार्टी के हितों को आगे बढ़ाने तथा वामपंथी व जनतांत्रिक शक्तियों को गोलबंद करने को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बहरहाल, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ किसी राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है।

वामपंथी आधार क्षेत्र

2.94 21वीं कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव ने पश्चिम बंगाल में लगे धक्कों की रौशनी में पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में पार्टी तथा वामपंथ के आधार की हिफाजत करने के महत्व को रेखांकित किया था। उसके बाद से भाजपा वामपंथी नेतृत्ववाले राज्यों, केरल तथा त्रिपुरा को निशाना बनाए रही थी। उसके बाद से भाजपा ने त्रिपुरा में चुनाव जीत लिया है और चुनाव के नतीजे आने के बाद से बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, जिनका मकसद पार्टी तथा वामपंथी आंदोलन को कुचलना है। भाजपा, केरल को भी निशाना बना रही है जहां एलडीएफ सरकार के सत्ता में आने के बाद से, पार्टी के दफ्तरों तथा कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ गए हैं।

2.95 इस मुकाम पर पार्टी और पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में उसके आधार क्षेत्रों की हिफाजत करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम आवश्यक सांगठनिक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि हमलों को विफल किया जा सके, पार्टी संगठन की हिफाजत की जा सके और जनता के साथ रिश्ते बनाए रखे जा सकें तथा उनका विस्तार किया जा सके।

केरल

2.96 सी पी आइ (एम) और एलडीएफ ने 2016 की मई में केरल विधानसभा के चुनाव में 140 में से 91 सीटें हासिल कर जीत दर्ज करायी। एलडीफ को 43.35 फीसद वोट मिले, जबकि यूडीएफ को 38.8 फीसद वोट मिले। इसके साथ ही भाजपा और उसके सहयोगियों को मिलकर, 15 फीसद वोट मिले। एलडीएफ सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र के अनेक वादों को लागू कर दिया है। उसने सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 600 रु0 प्रतिदिन कर दिया है। उसने लोगों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पेंशनों को बढ़ा दिया है। वह सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और उन्नत बनाने के लिए कदम उठा रही है। उसने मंदिर के पुजारियों के पदों पर अनुसूचित जातियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। इस सरकार ने चार मिशन शुरू किए हैं: (1) जीवन—गृहहीनों को आवास देना; (2) अर्द्रम—मुकम्मल स्वास्थ्य रक्षा परियोजना; (3) सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों को उन्नत करना; और (4) हरित केरलम—मुकम्मल सेनिटेशन, ऑर्गनिक खेती तथा नदियों व वाटरशैडों की हिफाजत के लिए हरित मिशन।

2.97 एलडीएफ के सरकार में आने के बाद से, आरएसएस ने सी पी आइ (एम) कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में 13 कामरेड मारे गए हैं और 200 से ज्यादा पार्टी सदस्य तथा हमदर्द घायल हुए हैं। 2000 से ज्यादा घरों तथा करीब 50 पार्टी कार्यालयों पर भी हमले किए गए हैं, उनमें आग लगायी गयी है या तोड़ा-फोड़ा गया है।

2.98 आरएसएस और भाजपा, सी पी आइ (एम) तथा एलडीएफ के खिलाफ, आरएसएस-भाजपा के कार्यकर्ताओं को सफाया करने के लिए निशाना बनाने का झूठा आरोप लगाते हुए, अखिल भारतीय अभियान चला रहे हैं। पार्टी और एलडीएफ ने, भाजपा-आरएसएस जोड़ी के झूठ का जवाब देने के लिए एक जोरदार जन अभियान छेड़ा है। ऐसे मुकाम पर कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ, एलडीएफ का विरोध करने के लिए, भाजपा से होड़ कर रहा है।

त्रिपुरा

2.99 फरवरी, 2018 में हुए त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव में वाम मोर्चा हार गया और भाजपा-आइपीएफटी सरकार बन गयी। यह सी पी आइ (एम) और वामपंथी तथा जनतांत्रिक ताकतों के लिए एक बड़ा धक्का है। भाजपा-आइपीएफटी गठजोड़ को 43 सीटों तथा 50.5 फीसद वोट के साथ, दो-तिहाई बहुमत हासिल हो गया। वाम मोर्चा को 44.9 फीसद वोट मिला और 16 सीटें मिलीं। पिछले विधानसभाई चुनाव की तुलना में उसके वोट में 7.45 फीसद की कमी हुई है।

2.100 वाम मोर्चा 1993 से लगाकर 25 साल से लगातार यहां सरकार में था। वाम मोर्चा सरकार ने राज्य में विकास के काम और सामाजिक कल्याण के कदमों को आगे बढ़ाया था, जिसने त्रिपुरा को उत्तर-पूर्व में एक मॉडल के रूप में उभारा था। उसने सामाजिक सूचकों के मामले में एक ईर्ष्या के योग्य रिकार्ड कायम किया था। इस सरकार ने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के हिस्से में 62 फीसद की कमी की थी। स्वायत्त जिला परिषद के तहत, जिसका गठन छठी अनुसूची के अंतर्गत किया गया था, आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित किए गए थे।

2.101 लेकिन, इस चौतरफा अच्छे रिकार्ड के बावजूद, भाजपा तमाम वामपंथविरोधी ताकतों को एकजुट कर, समर्थन जुटाने में कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी को भाजपा ने करीब-करीब पूरी तरह से हड़प कर लिया। भाजपा ने आइपीएफटी के साथ गठजोड़ किया जिसके आदिवासियों के लिए पृथक राज्य के नारे का आदिवासी जनता के बीच और खासतौर पर युवाओं के बीच कुछ असर था। परिवर्तन के नारे और भाजपा तथा प्रधानमंत्री के दरियादिली के वादों ने जनता के एक हिस्से को आकर्षित किया था। उन्होंने जो पैसा बहाया उससे वे विपक्षी कार्यकर्ताओं को अपने पाले में करने में और मतदाताओं के कुछ हिस्सों के प्रभावित करने में कामयाब रहे। इसकी गहराई से पड़ताल करनी होगी कि पार्टी का आदिवासी आधार कैसे छीज गया; क्या सांगठनिक कमियां रहीं और स्थानीय निकायों के प्रदर्शन का क्या असर पड़ा?

2.102 चुनाव के बाद के हालात में हमारी पार्टी और जनसंगठनों को व्यापक पैमाने पर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों पार्टी दफ्तरों पर हमले हुए हैं, उन्हें जलाया गया है या तोड़ा-फोड़ा गया है; हमारे कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों

के घरों पर हमले किए जा रहे हैं; ट्रेड यूनियन दफ्तरों पर कब्जा किया गया है या उन्हें नष्ट किया गया है। पंचायतों व स्थानीय निकायों पर कब्जा किया जा रहा है या सदस्यों को इस्तीफा देने या फिर दलबदल करने के लिए मजबूर कर के इन संस्थाओं को पंगु बनाया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि पार्टी को पंगु किया जाए और उसके जनाधार को आतंकित किया जाए। पार्टी और वाम मोर्चा, इस हिंसक अभियान के सामने मजबूती से डटे रहेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए, हमलों का प्रतिरोध करने के लिए जनता को गोलबंद करने के लिए और जनता के साथ जीवंत रिश्ते बनाए रखने के लिए, पार्टी और वाम मोर्चा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल

2.103 तृणमूल कांग्रेस निजाम ने सी पी आइ (एम) तथा वाम मोर्चा को निशाना बनाते हुए, अपने आतंक के निजाम तथा फासिस्टी प्रकृति के हमलों को जारी रखा है। 2016 के विधानसभाई चुनाव के बाद से तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी के खिलाफ व्यापक पैमाने पर हमले किए हैं। ये हमले खासतौर पर उन इलाकों में किए गए हैं, जहां पार्टी ने अपने जनाधार को बनाए रखा है। 2016 के जून के बाद से, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे 31 सी पी आइ (एम) सदस्यों तथा समर्थकों की हत्या कर चुके हैं। जिस एक और पैंतरे का सहारा लिया जा रहा है, वह है ऐसी पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों तथा नगर निकायों पर जबरन कब्जा करना, जहां सी पी आइ (एम) का बहुमत था। धमकियों तथा हमलों के चलते हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। 2018 के पंचायत चुनावों में, वाम मोर्चा तथा विपक्षी उम्मीदवारों को नामजदगी के पर्चे भरने से रोकने के लिए, व्यापक पैमाने पर हमलों तथा हिंसा का सहारा लेकर, चुनाव-पूर्व धांधली की गयी है।

2.104 पार्टी ने जनता के साथ अपने रिश्तों में नयी जान डालने की एक योजना तैयार की है। पार्टी, वाम मोर्चा तथा जनसंगठनों द्वारा अनेक जत्थों तथा पदायात्राओं का आयोजन किया गया है। किसानों तथा खेत मजदूर संगठनों ने नबान्न मार्च आयोजित किया है। ताजातरीन अभियान जनसंगठनों के बंगाल मंच (बीपीएमओ) का रहा है, जिसने अधिकांश ब्लाकों तथा मतदान केंद्रों तक पदयात्राओं तथा जत्थों का आयोजन किया है।

2.105 प्रकटत: भाजपा का विरोध करने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस ऐसी मुद्राएं अपना

रही है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को ही आसान बनाती हैं। वह इस तरह से वामपंथ को हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रही है। पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के जनतंत्रविरोधी निजाम और भाजपा की सांप्रदायिक तिकड़मों, दोनों का मुकाबला कर रही है।

पार्टी ने, पार्टी संगठन को चुस्त-दुरुस्त बनाने और पार्टी सदस्यता की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि पार्टी संगठन इन जटिल हालात में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके।

पार्टी की स्वतंत्र ताकत

2.106 पार्टी की स्वतंत्र शक्ति में बढ़ोतरी, पार्टी के आगे बढ़ने और वामपंथी तथा जनतांत्रिक मोर्चे के निर्माण की कुंजी है। पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में लगे धक्कों और केरल को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रगति के अभाव के चलते यह और भी जरूरी हो गया है। पार्टी के आधार तथा प्रभाव का विस्तार करने के जरिए ही हम वामपंथी तथा जनतांत्रिक विकल्प की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए, जनता के साथ जीवंत रिश्ते गढ़ने तथा वर्गीय व जन संघर्षों का विकास करने और इन्हें राजनीतिक प्रभाव के रूप में सुदृढ़ करने के लिए, चौतरफा तथा सतत प्रयास की जरूरत है।

2.107 सत्ताधारी वर्ग की विचारधारा तथा राजनीति की काट करने के लिए पार्टी को जोर-शोर से राजनीतिक तथा विचारधारात्मक अभियान चलाने होंगे। पार्टी को, सामाजिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करना चाहिए और संघर्षों को हाथ में लेना चाहिए। जन तथा वर्गीय संगठनों को जनता के वृहत्तर तबकों की गोलबंदी के लिए मंच बनना चाहिए ताकि उन्हें सतत आंदोलनों और व्यापक आधार वाले संघर्षों के लिए संगठित किया जा सके।

वामपंथी एकता

2.108 पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा के अलावा अनेक राज्यों में वामपंथी पार्टियों की संयुक्त कार्रवाइयां हो रही हैं। इस सिलसिले में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, असम तथा पंजाब उल्लेखनीय हैं। फिर भी, कुछ वामपंथी पार्टियों के भिन्न-भिन्न राजनीतिक रुखों को देखते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त गतिविधियां चलाने तथा उन्हें और मजबूत करने में कठिनाइयां रही हैं। आरएसपी तथा फारवर्ड ब्लाक की केरल राज्य इकाइयां, कांग्रेस के नेतृत्ववाले

यूडीएफ में हैं। सी पी आइ ने ऐसी राजनीतिक लाइन अपनायी है जो कांग्रेस समेत, सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ एकजुट होने की वकालत करती है।

2.109 एक अंतराल के बाद, नोटबंदी की पहली सालगिरह पर और 2017 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस की 25वीं सालगिरह पर, एकजुट कार्रवाई के आह्वान किए गए थे। जन संगठनों तथा सामाजिक आंदोलनों के संयुक्त मंच पर, कुछ साझा समझदारी पर भी पहुंचा गया है। हमें, वामपंथी एकता के लिए, साझा राजनीतिक नजरिए के आधार पर, सिद्धांतनिष्ठ संघर्ष चलाना चाहिए।

वामपंथी तथा जनतांत्रिक मोर्चा

2.110 21वीं कांग्रेस ने वामपंथी तथा जनतांत्रिक मोर्चे की प्रधानता बहाल करने का आह्वान किया था। यही मोर्चा है, जो पूंजीवादी-भूस्वामी नीतियों का वास्तविक विकल्प है। राजनीतिक प्रस्ताव में ऐसे मोर्चे की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी थी: ''इस समय वामपंथी तथा जनवादी मोर्चे में खींची जा सकने वाली शक्तियों के केंद्र में हैं वामपंथी पार्टियां तथा उनके वर्गीय व जनसंगठन; वामपंथी ग्रुप तथा बुद्धिजीवी; विभिन्न पार्टियों में बिखरे हुए समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी पार्टियों के जनतांत्रिक हिस्से; आदिवासियों, दलितों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के जनतांत्रिक संगठन और ऐसे सामाजिक आंदोलन जो उत्पीड़ित तबकों के मुद्दे उठाते हैं। पूंजीवादी-भूस्वामी पार्टियों से बिल्कुल भिन्न तथा उनकी नीतियों के विरोधी कार्यक्रम पर आधारित संयुक्त मंच पर इन सभी ताकतों को खींचने के जरिए ही, वामपंथी तथा जनतांत्रिक मोर्चे की दिशा में प्रगति एक ठोस रूप ले सकती है।''

2.111 जन एकता, जन अधिकार आंदोलन के गठन के जरिए, जो विभिन्न वर्गीय संगठनों, जन संगठनों तथा सामाजिक आंदोलनों का एक मंच है, इस दिशा में एक कदम उठाया गया है। इसे एक शक्तिशाली साझा मंच बनाने के लिए, जो देशव्यापी एकजुट संघर्ष छेड़ने में समर्थ हो, और प्रयास करने की जरूरत है। हमारे प्रयास इन एकजुट संघर्षों को, जो एक वामपंथी तथा जनतांत्रिक विकल्प के निर्माण में योगदान कर सकते हैं, आगे बढ़ाने के होने चाहिए।

2.112 सभी राज्यों में इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि संबंधित राज्य के लिए प्रासंगिक एक कार्यक्रम के गिर्द वामपंथी तथा जनतांत्रिक शक्तियों को एक साथ लाया जाए। इसमें पार्टियां, जन संगठन, जनतांत्रिक संगठन, सामाजिक आंदोलन तथा बुद्धिजीवी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर,

एकजुट वामपंथी मंचों के जरिए, वामपंथी तथा जनतांत्रिक विकल्प को सामने लाया जाना चाहिए।

2.113 चूंकि इसे लंबे अर्से से प्रचार के नारे की तरह ही लिया जा रहा था, समूची पार्टी को आने वाले दिनों में प्राथमिकता के तौर पर इस काम को हाथ में लेने के लिए शिक्षित करना होगा।

वामपंथी तथा जनतांत्रिक कार्यक्रम: एक विकल्प

2.114 वामपंथी तथा जनतांत्रिक कार्यक्रम, नवउदारवाद तथा पूंजीपति-भूस्वामी वर्ग की नीतियों की वैकल्पिक नीतियां पेश करता है। इनमें मजदूर वर्ग, किसान जनता, ग्रामीण श्रमिकों तथा मेहनतकश जनता के अन्य तबकों की बुनियादी मांगें शामिल हैं। इन व्यापक मुद्दों तथा मांगों को, वामपंथी तथा जनतांत्रिक ताकतों को गोलबंद करने के लिए ठोस रूप दिया जा सकता है, ताकि वामपंथी तथा जनतांत्रिक विकल्प को सामने लाया जाए और वर्गीय संघर्षों तथा जन आंदोलनों को खड़ा किया जाए।

2.115 इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है:

1. **धर्मनिरपेक्षता:** धर्मनिरपेक्षता के एक बुनियादी सिद्धांत के तौर पर धर्म तथा राज्य के अलगाव का संविधान में मूर्त किया जाना; धार्मिक सांप्रदायिकता तथा जातिवादी उन्माद पर आधारित नफरत की मुहिम को गैर-कानूनी बनाने के लिए कानून बनाना; आरएसएस के लोगों को राजकीय संस्थाओं से हटाना।

2. **संघवाद:** राज्यों को और शक्तियां देते हुए केंद्र-राज्य संबंधों का पुनर्गठन; इस काम के लिए समवर्ती सूची में संशोधन। धारा-356 को उपयुक्त प्रावधान से बदलना; राज्यपालों की भूमिका को सुधारना; धारा-370 को बहाल करने के जरिए जम्मू-कश्मीर को अधिकतम स्वायत्तता देना; निर्वाचित स्थानीय निकायों को और ज्यादा शक्तियां तथा काम सौंपना।

3. **जनतंत्र:** नागरिकों के जनतांत्रिक अधिकारों का विस्तार करना; सशस्त्र बल विशेष शक्तियां कानून (अफस्पा) तथा गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण कानून (यूएपीए) को निरस्त करना; भारतीय दंड संहिता से राजद्रोह की धारा को हटाना; मौत की सजा खत्म करना; धन-बल पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव सुधार; आंशिक सूची प्रणाली के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू

करना।

4. आर्थिक नीति और विकास

(1) संतुलित तथा आत्मनिर्भर विकास को आगे ले जाने के लिए नियोजन की बहाली; उत्पादक शक्तियों का विकास करना, रोजगार पैदा करना और आर्थिक व सामाजिक असमानताएं घटाना।

(2) बुनियादी भूमि सुधार लागू करना तथा कृषि संबंधों का जनतांत्रिक रूपांतरण सुनिश्चित करना ; भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के बीच भूमि का वितरण; सहकारी खेती व मार्केटिंग का विकास।

(3) निजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का पुनर्राष्ट्रीयकरण करना; बुनियादी सेवाओं में जैसे बिजली, जल आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन तथा स्वास्थ्य व शिक्षा के निजीकरण को पलटवाना; इजारेदारियों पर अंकुश लगाना; संपदा के पुनर्वितरण के लिए राजकोषीय तथा कर संबंधी कदम; काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम; वित्तीय प्रवाहों का नियमन करना; लघु तथा मंझले उद्योगों को बढ़ावा देना और परंपरागत उद्योगों की रक्षा करना।

5. मेहनतकश जनता के अधिकार

(1) **मजदूर वर्ग:** मजदूरों के लिए कम से कम 18,000 रु0 महीना की वैधानिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना तथा मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना; गुप्त मतदान के जरिए ट्रेड यूनियनों को मान्यता दिया जाना सुनिश्चित करना; सामाजिक सुरक्षा तथा प्रबंधन में मजदूरों की हिस्सेदारी की गारंटी। रोजगार के ठेकाकरण का अंत।

(2) **किसान:** खेती की पैदावार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर उत्पादन लागत से 50 फीसद ज्यादा देना; छोटे तथा मंझले किसानों के लिए ऋण राहत के कदम; छोटे तथा मंझले किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण कर्ज माफी, गैर-कृषि कार्यों के लिए जबरिया तथा अंधाधुंध अधिग्रहण से खेती की भूमि की हिफाजत; कार्पोरेट खेती तथा निजीकरण पर रोक।

(3) **खेतमजदूर:** खेतमजदूरों के लिए मजदूरी व सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रीय कानून; ग्रामीण मजदूरों के लिए घर बनाने के लिए जमीन और आवास;

मनरेगा का विस्तार तथा कड़ाई से पालन।

6. **जनकल्याण:** खाद्यान्नों के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी आपूर्ति के साथ सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वभौम पेंशन लाभ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था। पीने के लिए सुरक्षित पानी तथा जल-मल निकासी की व्यवस्था। शहरी तथा ग्रामीण गरीबों के लिए आवास। सस्ते सार्वजनिक परिवहन का विस्तार। काम, शिक्षा तथा स्वास्थ्य का अधिकार।

7. **लैंगिक समानता:** संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान। महिलाओं व बच्चों के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को रोकने, उन पर अंकुश लगाने तथा उनके दोषियों को सजा दिलाने के लिए कदमों का लागू किया जाना। समान काम के लिए समान मजदूरी; ट्रांसजैंडरों के अधिकार।

8. सामाजिक न्याय और नागरिकों के अधिकार

(1) **दलित:** जाति व्यवस्था तथा हर प्रकार के जातिवादी उत्पीड़न का अंत। छुआछूत के व्यवहार तथा अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचारों के लिए कड़ी सजा। आरक्षित सीटों पर, पदों पर तथा पदोन्नतियों में बैकलॉग का भरा जाना। दलित ईसाइयों के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा। निजी क्षेत्र में आरक्षण।

(2) **सबसे पिछड़े वर्ग:** शिक्षा व रोजगार में समुचित आरक्षण सुनिश्चित करना; सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए व्यवस्थाएं।

(3) **आदिवासी:** आदिवासियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा और उनसे हथियाई गयी जमीनें उन्हें वापस दिलाना। वनाधिकार कानून का पूरा-पूरा पालन। लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। आदिवासियों की भाषाओं तथा संस्कृतियों के लिए संरक्षण। पांचवीं तथा छठी अनुसूचियों तथा पंचायत (एक्स्टेंशन टु दी शिड्यूल्ड एरियाज) एक्ट, 1996 की हिफाजत।

(4) **अल्पसंख्यक:** अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अपराधों के लिए कड़ी सजा; मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण के विशेष प्रावधान।

(5) **विकलांग:** समान अवसर तथा मैदान में बराबरी के मौके; सभी सार्वजनिक जगहों, परिवहन, संचार, मनोरंजन तक बाधामुक्त पहुंच।

(4) **युवाओं तथा बच्चों के अधिकार:** संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में काम का अधिकार। युवाओं के चौतरफा विकास के लिए सेवाओं का—खेलकूद, सांस्कृतिक व कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान। बाल श्रम के सभी रूपों पर प्रतिबंध। 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास योजना (आइसीडीएस)/शिशु देख-रेख की सार्वभौम व्यवस्था।

9. **शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण**

(1) सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का विस्तार तथा उसकी गुणवत्ता को ऊपर उठाना ताकि सबके लिए शिक्षा को पहुंच में लाया जा सके; पाठ्यचर्या तथा विषयों में संशोधन ताकि अंतर्वस्तु को धर्मनिरपेक्ष बनाया जा सके तथा वैज्ञानिक सोच पनप सके; निजी शैक्षणिक संस्थाओं में फीस तथा पाठ्यक्रम का नियमन।

(2) केंद्रीय व राज्य सरकारों की फंडिंग के साथ एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण, जो मुफ्त स्वास्थ्य रक्षा मुहैया करा सके। इसे सुगम बनाने के लिए, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 5 फीसद के बराबर किया जाए। निजी स्वास्थ्य केंद्रों का नियमन किया जाए; आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाया जाए।

(3) कारगर नियमन, उत्पादन व उपभोग के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा कुशलता लाने के जरिए, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए कदम उठाए जाएं। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए; ऊर्जा असमानता को घटाया जाए। नदियों, सागरों व अन्य जलाशयों के प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाए। विशेष रूप से वनों की रक्षा तथा दलदली जमीनों का संरक्षण किया जाए।

10. **संस्कृति और मीडिया:** प्रतिगामी सांप्रदायिक तथा पोंगापंथी प्रभावों की काट करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष तथा मिली-जुली संस्कृति का विकास; लोक कलाओं तथा परंपराओं का पोषण; सभी भाषाओं के लिए बराबरी का दर्जा; उर्दू का बढ़ावा तथा कुछ राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में उसकी मान्यता।

सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को मजबूत करना। मीडिया में एकाधिक क्षेत्रों में स्वामित्व पर रोक। मीडिया के लिए एक स्वतंत्र नियमन प्राधिकार।

11. **विदेश नीति:** अमरीका के साथ रणनीतिक गठजोड़ को पलटना; साम्राज्यवादविरोधी तथा स्वतंत्र विदेश नीति।

राजनीतिक लाइन

2.116 (1) मोदी सरकार के करीब चार साल के अनुभव को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि भाजपा की सरकार को शिकस्त दी जाए ताकि हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक ताकतों को अलग-थलग किया जा सके और जनविरोधी आर्थिक नीतियों को पलटा जा सके।

(2) इसलिए, मुख्य काम है तमाम धर्मनिरपेक्ष तथा जनतांत्रिक शक्तियों को गोलबंद कर, भाजपा और उसके सहयोगियों को पराजित करना।

(3) लेकिन, यह कांग्रेस पार्टी के साथ कोई राजनीतिक गठबंधन किए बिना करना होगा।

(4) बहरहाल, सहमति के मुद्दों पर संसद में, कांग्रेस समेत तमाम धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों के साथ सहयोग तालमेल किया जा सकता है। संसद के बाहर हमें, सांप्रदायिकता के खिलाफ जनता की व्यापक गोलबंदी के लिए तमाम धर्मनिरपेक्ष विपक्षी ताकतों के साथ सहयोग करना चाहिए। हमें वर्गीय व जनसंगठनों की संयुक्त कार्रवाइयों को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, जो कांग्रेस तथा अन्य पूंजीवादी पार्टियों के पीछे चलने वाले अवाम को अपनी ओर खींच सके।

(5) पार्टी, नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ेगी जिन पर केंद्र में भाजपा की सरकार सरकार चल रही है और विभिन्न राज्य सरकारें चल रही हैं, जिनमें क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा चलायी जा रही सरकारें भी शामिल हैं। पार्टी, जनता की रोजी-रोटी के मुद्दों पर और आर्थिक नीतियों के हमले के खिलाफ एकजुट तथा सतत कार्रवाइयों का विकास करने का प्रयत्न करेगी।

(6) हर स्तर पर जनसंगठनों के संयुक्त मंचों तथा एकजुट संघर्षों का निर्माण किया जाना चाहिए। जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज किया जाना चाहिए। वर्गीय तथा जनसंगठनों की एकजुट कार्रवाइयों को, पूंजीवादी पार्टियों के पीछे चलने वाली जनता को खींचने का प्रयास करना

चाहिए।

(7) सरकार के अंदर से और सरकार से बाहर से भी, हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा पेश की जा रही गंभीर चुनौती को देखते हुए, यह जरूरी है कि तमाम धर्मनिरपेक्ष तथा जनतांत्रिक शक्तियों व्यापकतम गोलबंदी के लिए मंचों का निर्माण किया जाए। जोर इस पर रहना चाहिए कि आम जनता के स्तर पर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए जनता की एकता का निर्माण किया जाए। इन्हें राजनीतिक या चुनावी गठबंधनों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसी प्रकार, जनतांत्रिक अधिकारों पर तानाशाहीपूर्ण हमलों के खिलाफ लड़ने के लिए, व्यापक एकता का निर्माण किया जाना चाहिए।

(8) पार्टी की स्वतंत्र शक्ति का निर्माण तथा विकास करने को, पार्टी प्राथमिकता देगी। वह वामपंथी एकता को व्यापक बनाने तथा मजबूत करने के लिए काम करेगी।

(9) तमाम वामपंथी तथा जनतांत्रिक ताकतों को, एकजुट संघर्षों तथा संयुक्त आंदोलनों को चलाने के लिए एक ठोस कार्यक्रम पर एक साथ लाया जाना चाहिए। इसके जरिए वामपंथी तथा जनतांत्रिक मोर्चे का उदय हो सकता है। राज्यों में, किसी ठोस कार्यक्रम के गिर्द एक मंच के गठन के लिए, विभिन्न वामपंथी तथा जनतांत्रिक शक्तियों को गोलबंद किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे राजनीतिक अभियानों में और ऐसी तमाम ताकतों को गोलबंद करने में, जो वामपंथी तथा जनतांत्रिक मोर्चे में जगह ले सकती हों, वामपंथी तथा जनतांत्रिक विकल्प को सामने लाया जाना चाहिए।

(10) पार्टी की उपरोक्त राजनीतिक लाइन के आधार पर, भाजपा-विरोधी वोट की एकता को अधिकतम करने के लिए, समुचित चुनावी कार्यनीति अपनायी जानी चाहिए।

मौजूदा हालात में काम

2.117 (1) मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाना चाहिए। नवउदारवादी नीतियों के शोषण तथा हमलों के शिकार हो रहे मेहनतकश जनता के सभी तबकों को रोजगार, भूमि, भोजन, मजदूरी तथा रोजी-रोटी के लिए लड़ने के वास्ते गोलबंद तथा संगठित किया जाना चाहिए। पार्टी को, जो भी स्वत:स्फूर्त संघर्ष विकसित होते हैं, उनमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें आगे ले जाना चाहिए।

(2) पार्टी और जनसंगठनों को, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष में अगली पंक्ति में रहना होगा। यह संघर्ष सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा विचारधारात्मक क्षेत्रों में चलाना होगा। सांप्रदायिक ताकतों की गतिविधियों की काट करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक ताकतों का एक व्यापक मंच खड़ा किया जाना चाहिए।

(3) पार्टी को, सामाजिक रूप से उत्पीड़ित तबकों के हितों को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों को तेज करना चाहिए। पार्टी को अविचल रूप से महिलाओं के अधिकारों का झंडा उठाना होगा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की काट करनी होगी। दलित अधिकारों की हिमायत में वामपंथी तथा दलित, एकजुट मंचों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पार्टी को सभी क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, व्यापक एकता कायम की जानी चाहिए।

(4) पार्टी को, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए और देश में बढ़ते साम्राज्यवादी प्रभाव के खिलाफ, जिसे अमरीका के साथ रणनीतिक गठजोड़ सुगम बना रहा है, जनता को गोलबंद करने के लिए अपने अभियानों का विस्तार करना होगा। उसे भाजपा की अति-राष्ट्रवादी मुद्रा को बेनकाब करना चाहिए, जिसका इस्तेमाल अमरीकी साम्राज्यवाद की मातहती पर पर्दा डालने के लिए किया जाता है।

(5) बढ़ती तानाशाही तथा फासिस्टी हमलों की काट करने के लिए पार्टी को व्यापकतम शक्तियों को गोलबंद करना होगा। जनतंत्र पर, कलात्मक स्वतंत्रता पर तथा अकादमिक स्वायत्तता पर हमलों के खिलाफ व्यापक गोलबंदी होनी चाहिए।

(6) पार्टी को, वर्गीय व जन संघर्षों का निर्माण करने के जरिए, अपनी स्वतंत्र भूमिका को मजबूत करने और अपने प्रभाव व जनाधार का विस्तार करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। पार्टी को, पश्चिम बंगाल में जनतंत्र पर हमलों और पार्टी व वाम मोर्चा के खिलाफ हिंसा के विरुद्ध संघर्ष पर विशेष ध्यान देना होगा। केरल में वामपंथी तथा जनतांत्रिक मोर्चा सरकार का बचाव, एक महत्वपूर्ण काम है।

(7) एक वामपंथी मंच के आधार पर, संयुक्त कार्रवाइयों तथा अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के जरिए, मौजूदा कमजोरियों से उबरते हुए, वामपंथी

एकता को मजबूत किया जाना चाहिए। इसे, एक वामपंथी तथा जनतांत्रिक कार्यक्रम के गिर्द, अन्य जनतांत्रिक संगठनों तथा शक्तियों को खींचने का आधार होना चाहिए। ऐसे एक कार्यक्रम के गिर्द आंदोलनों तथा संघर्षों के जरिए ही, एक वास्तविक विकल्प, वामपंथी तथा जनतांत्रिक विकल्प उभरेगा।

मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करो

2.118 इस काम को पूरा करने के लिए जरूरी है कि देश भर में एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी की जाए। यह ऐसी पार्टी होनी चाहिए, जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद पर आधारित हो और जनवादी-केंद्रीयता के सिद्धांतों पर संगठित हो। एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, जिसका जनाधार देश भर में फैला हुआ हो, हमें कोलकाता प्लेनम द्वारा तय किए गए सांगठनिक कामों को पूरा करना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित हो:

1) आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर वर्गीय तथा जन संघर्ष निर्मित करना ताकि पार्टी के प्रभाव का विस्तार किया जा सके और वामपंथी व जनतांत्रिक शक्तियों को गोलबंद किया जा सके।

2) एक जन लाइन को अपनाना और जनता के साथ जीवंत रिश्ते कायम करना।

3) संगठन को चुस्त-दुरुस्त करना ताकि गुणवत्तापूर्ण सदस्यता के साथ एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण किया जा सके।

4) युवाओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष प्रसास करना।

5) सांप्रदायिकता, नवउदारवाद तथा प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं के खिलाफ विचारधारात्मक संघर्ष चलाना।

2.119 **आइए हम**

- भाजपा के तानाशाहीपूर्ण सांप्रदायिक निजाम को परास्त करने के लिए संघर्ष चलाएं!
- मजबूत सी पी आइ (एम) का निर्माण करें ताकि जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय तथा समाजवाद के लिए संघर्ष को आगे बढ़ा सकें!
- एक मजबूत वामपंथी तथा जनतांत्रिक मोर्चे का निर्माण करें ताकि एक वामपंथी तथा जनतांत्रिक विकल्प गढ़ सकें!

भारत की
कम्युनिस्ट
पार्टी
(मार्क्सवादी)

22वीं कांग्रेस का राजनीतिक प्रस्ताव

(18 से 22 अप्रैल 2018 तक हैदराबाद में संपन्न पार्टी कांग्रेस में स्वीकृत)

मई, 2018

मूल्य : 15 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लिए हरि सिंह कांग द्वारा ए के गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित (फोन : 22119770)